सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 123, नई दिल्ली । रविवार, 14 जुलाई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा ।

03 दिल्ली मूनक नहर तटबंध दुरूस्त, वाटर ट्रीटमेंट शुरू
06 कातिलाना शौक की आगोश में युवावेग
08 स्वामी तेजानन्द महाराज का किया भव्य स्वागत

यमराज बनकर सड़कों पर दौड़ रहीं महोबा में फर्जी तरीके से दर्ज 79 बसें, जांच में चौंकाने वाला खुलासा

उन्नाव हादसे में शिकार महोबा में दर्ज बस की जांच के बाद चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिनके नाम केयर ऑफ में दर्ज कराईं बसें उन्हें जानकारी ही नहीं है। बस माफिया का बड़ा सिंडीकेट सामने आने की आशंका जताई जा रही है।

परिवहन विशेष न्यूज

कानपुर। आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए एड्रेस के प्रूफ के लिए तमाम तरह के कागज मांगने वाले परिवहन विभाग को यह नहीं मालूम कि यमराज बनकर दौड़ रहीं इन स्लीपर बसों का असली मालिक कौन है। बस माफिया के सिंडीकेट ने अफसरों की आंखों में धूल झोंककर केयर ऑफ में पंजीयन करा दिया। बसें पूरे देश में दौड़ने लगीं। सिर्फ महोबा में केयर ऑफ में दर्ज 79 बसें एआरटीओ में पंजीकृत हैं। यह कभी उन्नाव नहीं आईं। उन्नाव में हादसे में 18 लोगों की जान न जाती तो यह खेल भी न खुलता।

एआरटीओ कार्यालय में तीन दिन से चल रही जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि जो बसें महोबा में केयर ऑफ में दर्ज हैं, वह कभी महोबा आई ही नहीं। ऐसे में इन बसों की फिटनेस कैसे जांची गई। उन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र देने में नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया, यह बड़ा सवाल है। बस माफियाओं का सिंडीकेट बड़ा है और दूर तक इसके तार जुड़े हैं। जनपद उन्नाव में जिस बस से हादसा हुआ वह राजस्थान के केसी जैन ट्रैवल्स के नाम से संचालित है जबकि बस मालिक की कोरोना के दौरान मौत हो चुकी है। बिहार का एक व्यक्ति बस को ठेके पर लेकर दिल्ली से संचालित करता है। यह बस कभी महोबा नहीं आई लेकिन देश के विभिन्न राज्यों में दौड़ती रही।

केयर ऑफ में मिलीं 40 अन्य बसों के ढूंढे जा रहे मालिक

दो दिन पहले उन्नाव में सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत व 19 लोगों के घायल होने के बाद महोबा के एआरटीओ कार्यालय के अधिकारियों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। उन्नाव में हादसे की शिकार बस महोबा में केयर ऑफ में खन्ना थाना क्षेत्र के मवईखुर्द गांव निवासी पुष्पेंद्र के नाम दर्ज है। शासन की ओर से नमित की गई जांच टीम की पड़ताल के दौरान गुरुवार को यह बात सामने आई थी कि पुष्पेंद्र और कबरई निवासी सत्यम अग्निहोत्री के नाम 39 बसें केयर ऑफ में दर्ज हैं। इन दोनों को पता ही नहीं ये बसें कब उनके नाम पर दौड़ रही हैं। इस बीच, शुक्रवार को भी एआरटीओ कार्यालय में बसों के पंजीयन से जुड़े दस्तावेजों की जांच पड़ताल का सिलसिला चला। 40 अन्य बसें जो केयर ऑफ में दर्ज हैं। उसकी पड़ताल जारी है।

जनप्रतिनिधियों ने दबाव बनाकर कराए थे पंजीयन

पिछले पांच साल से महोबा एआरटीओ कार्यालय में जनप्रतिनिधियों का दखल रहा। इन्हीं जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद होने के चलते बस संचालक माफिया एआरटीओ कार्यालय महोबा के अधिकारियों पर अपनी धौंस जमाकर मनचाहा काम करवाते रहे। इस तरह 79 बसें महोबा एआरटीओ कार्यालय में केयर ऑफ पर दर्ज हुईं। एआरटीओ कार्यालय में पूर्व में तैनात रहे एक अधिकारी ने नाम छापने की शर्त पर बताया कि जनप्रतिनिधियों के दबाव के कारण यहां अधिकतम केयर ऑफ के पते पर बसें दर्ज हुई हैं।

35 गाड़ियों के पंजीयन निलंबित

कबरई क्षेत्र के व्यक्तियों के नाम केयर आफ में दर्ज 39 बसें में 35 बसों के फिटनेस और परमिट समाप्त हो चुके हैं। इन 35 बसों के पंजीयन निलंबित कर दिए गए हैं जबकि केयर ऑफ में दर्ज चार बसों के फिटनेस व परमिट अभी वैध हैं। इन बसों के मालिक को एआरटीओ महोबा की ओर से पत्र भेजा गया है। बसों के पंजीयन में किए गए केयर ऑफ के खेल की परतें अब खुलने लगी हैं।

केयर ऑफ पर पूरी तरह से रोक

केयर ऑफ में 35 बसों का परमिट और फिटनेस समाप्त कर दिया गया है। इन बसों का पंजीकरण भी निलंबित कर दिया गया है। जांच अभी जारी है। पूर्व के अधिकारियों ने इन्हें केयर ऑफ में दर्ज कर लिया था। हालांकि, यह होना नहीं चाहिए। पूर्व के अधिकारी के खिलाफ शासन से अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। फिलहाल इस तरह के काम पर पूरी तरह रोक है।

हमारे मौलिक अधिकार: पर्यावरण के प्रति कर्तव्य और भारत में इसका मूल्यांकन

पर्यावरण का संरक्षण हमारे मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का अभिन्न अंग है। एक स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण न केवल हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। भारतीय संविधान में भी पर्यावरण संरक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है।

मौलिक अधिकार और पर्यावरण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को शामिल किया गया है, जो न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आवश्यक है बल्कि एक स्वस्थ पर्यावरण भी प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के भाग IV-A के अनुच्छेद 51A(g) में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करेगा, जिसमें वन, झील, नदी, और वन्यजीव शामिल हैं। इसके साथ ही, राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी भी दी गई है।

भारत में पर्यावरण संरक्षण के उपाय

कानूनी प्रावधान: भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कानूनी प्रावधान और अधिनियम लागू किए गए हैं, जैसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, आदि। ये अधिनियम पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने में मदद करते हैं।

न्यायिक सक्रियता: भारतीय न्यायपालिका ने कई बार पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। ताज ट्रेपेजियम केस, गोदावरी नदी प्रदूषण केस, और गंगा नदी की सफाई से जुड़े मामलों में उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किए हैं।

सिविल सोसाइटी और एनजीओ: विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये संगठन पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने, वृक्षारोपण, और स्वच्छता अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं।

सरकारी योजनाएं: सरकार ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे योजना, जल शक्ति अभियान, आदि। इन योजनाओं का उद्देश्य पर्यावरणीय संरक्षण और सुधार को बढ़ावा देना है।

पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियां

हालांकि भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, और कृषि की बदलती पद्धतियों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। प्रदूषण, वन कटाई, जल संसाधनों

का अव्यवस्थित उपयोग, और जैव विविधता की हानि जैसी समस्याएं अभी भी गंभीर हैं।

हमारे मौलिक अधिकारों के तहत स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार निहित है। लेकिन इस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहना होगा और अपने दैनिक जीवन में पर्यावरणीय दृष्टिकोण को अपनाना होगा। सरकार, न्यायपालिका, सिविल सोसाइटी, और प्रत्येक नागरिक को मिलकर इस दिशा में प्रयास करना होगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण प्रदान कर सकें। पर्यावरण संरक्षण न केवल हमारी जिम्मेदारी है बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

पर्यावरण और युवा शक्ति

प्रिय देशवासियों,

आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ हमारी युवा शक्ति बड़ी तेजी से विदेशों की ओर आकर्षित हो रही है। विदेश में शिक्षा प्राप्त करना, नौकरी करना या अवकाश बिताना एक सामान्य बात बन गई है। यह हमारे युवाओं की क्षमता और महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी उभरता है। हमारे युवा विदेश से लौटने के बाद अक्सर भारतीय राज्यों और पर्यावरण की तुलना अन्य देशों से करते हैं।

निस्संदेह, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है, लेकिन यह भी सच है कि इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हमारे ही देशवासी हैं। वर्तमान में हमारा भारत युवा है, और यह युवा शक्ति हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम अपने माता-पिता और समाज को साथ लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं।

हमारे देश की पर्यावरणीय स्थिति को सुधारने की जिम्मेदारी हम सभी पर है। यदि हम अपने घर, अपने समाज, अपने

राज्य और अपने देश को स्वच्छ और हरा-भरा नहीं बना सकते, तो विदेश जाकर भी हम पूर्ण संतोष नहीं पा सकेंगे।

हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का काम नहीं है, यह हम सभी का कर्तव्य है। हमें अपने देश में एक मजबूत और हरित उत्साही लोगों का नेटवर्क बनाना होगा। इससे हम न केवल अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य भी सुनिश्चित कर सकते हैं।

युवा शक्ति को अपने कर्तव्यों का एहसास कराना जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि हमारे छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे कदम उठाएं जैसे कि प्लास्टिक का कम उपयोग, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, और स्वच्छता अभियान में भाग लेना।

हम सभी को मिलकर एक हरित और स्वच्छ भारत का निर्माण करना होगा। यह हमारा राष्ट्र है और हमें इसे सुंदर और सुरक्षित बनाना है। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जहाँ हर युवा पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाए और दूसरों को भी प्रेरित करे।

आइए, हम सभी मिलकर एक हरित क्रांति का हिस्सा बनें और अपने देश को पर्यावरणीय संकट से उबारें। यह हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे निभाना होगा।

परिवहन विशेष : प्रस्तुत करता है पर्यावरण पाठशाला

डॉ. शरण की पहल 'पर्यावरण पाठशाला' का उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और उन्हें प्रकृति से जीवन की महत्वपूर्ण सीखें प्रदान करना। यह पहल केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों को सक्रिय रूप से पर्यावरण संरक्षण में भाग लेने के लिए प्रेरित भी करती है।

उनकी पर्यावरणीय उत्सुकता और संलग्नता के कारण, डॉ. शरण ने कई अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित किया है और भारत के पर्यावरण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे एक सशक्त ग्रीन एक्टिविस्ट हैं, जो हमारे समाज को हरित और स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

"पर्यावरण पाठशाला" के माध्यम से हम सभी को प्रेरित होकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए और डॉ. अंकुर शरण जैसे नायकों से सीख लेनी चाहिए।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

युवा शक्ति और पर्यावरण के प्रति उदासीनता के कारण

हमारे देश की युवा शक्ति अत्यंत प्रतिभाशाली और मेहनती है। वे अपने करियर और व्यक्तिगत विकास के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन जब बात पर्यावरण को सुधारने और संरक्षित करने की आती है, तो अधिकतर युवा इसमें उतनी रुचि नहीं दिखाते। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिन पर हमें विचार करना चाहिए।

पर्यावरण के प्रति उदासीनता के कारण

जानकारी और जागरूकता की कमी: बहुत से युवा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूक नहीं हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि उनके छोटे-छोटे प्रयासों का पर्यावरण पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।

तात्कालिक लाभ की अनुपस्थिति: पर्यावरण के लिए किए गए कार्यों के परिणाम तुरंत नहीं दिखते। यह एक लंबी अवधि का प्रयास है, जिसके लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलते हैं। यह तात्कालिक लाभ की कमी युवाओं को निराश करती है।

संवेदनशीलता की कमी: पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता की कमी भी एक बड़ा कारण है। युवाओं को यह महसूस नहीं होता कि पर्यावरण का संरक्षण उनके स्वयं के भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

समय और संसाधनों की कमी: अपने करियर और पढ़ाई में व्यस्त युवा अक्सर पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए समय और संसाधन नहीं निकाल पाते।

समूह प्रभाव: यदि युवाओं का समूह पर्यावरणीय गतिविधियों में सक्रिय नहीं है, तो व्यक्तिगत रूप से भी वे इसमें भाग नहीं लेते। समूह प्रभाव का भी बड़ा महत्व होता है।

मेरा अनुभव

व्यक्तिगत रूप से, मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहा हूँ। इपार्यावरण पाठशालाइ के माध्यम से मैं पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने की कोशिश करता हूँ। इस अभियान का उद्देश्य है लोगों को प्रकृति से सीखने और उसका सम्मान करने के लिए प्रेरित करना। मैं हमेशा से यह मानता हूँ कि छोटे-छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं।

कई बार मैंने देखा है कि जब युवा पर्यावरणीय गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो वे न केवल पर्यावरण की रक्षा करते हैं बल्कि स्वयं में भी एक नई ऊर्जा और संतुष्टि महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए,

मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वृक्षारोपण अभियान चलाया। यह अनुभव न केवल हमें प्रकृति के करीब लाया बल्कि हमें यह भी सिखाया कि सामूहिक प्रयासों से कैसे बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं।

समाधान

जागरूकता अभियान: स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में पर्यावरणीय जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। इसके लिए वर्कशॉप, सेमिनार, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है।

प्रेरणा स्रोत: युवाओं को प्रेरित करने के लिए उन लोगों की कहानियाँ बताई जानी चाहिए जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे उन्हें प्रेरणा मिलेगी और वे भी इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे।

समूह गतिविधियाँ:

युवाओं को पर्यावरणीय गतिविधियों में शामिल करने के लिए समूह गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। इससे न केवल उन्हें मज़ा आएगा बल्कि वे अपनी भागीदारी को भी गंभीरता से लेंगे।

सरकारी और गैर-सरकारी सहयोग:

सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को मिलकर ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए जिनमें युवाओं की सक्रिय भागीदारी हो। इससे उन्हें सही दिशा-निर्देश और संसाधन मिलेंगे।

प्रोत्साहन और सम्मान:

पर्यावरणीय गतिविधियों में भाग लेने वाले युवाओं को प्रोत्साहन और सम्मान दिया जाना चाहिए। इससे अन्य युवा भी प्रेरित होंगे।

युवा शक्ति हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। यदि वे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं, तो हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित और स्वस्थ बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम उन्हें सही जानकारी, प्रेरणा और प्रोत्साहन दें।

पर्यावरण संरक्षण का काम हम सबका है, और इसमें युवाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए, हम सब मिलकर एक स्वस्थ और सुंदर पर्यावरण की दिशा में कदम बढ़ाएं।

यदि आपके पास पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कोई कहानी या अनुभव है, तो कृपया हमें indiangreenbuddy@gmail.com पर साझा करें। हम आपके अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाने में खुशी महसूस करेंगे।

यंग भारतीय लड़कियों पर तेजी से अटैक कर रहा है ब्रेस्ट कैंसर ! रिपोर्ट में सामने आए डरावने तथ्य

दुनिया भर में जिस कैंसर से महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, वही कैंसर अब भारत में पहले से कहीं अधिक तेजी से पांव पसार रहा है. भारतीय महिलाओं, खासतौर से युवा लड़कियों और महिलाओं में, ब्रेस्ट कैंसर (स्तर कैंसर) के केस ज्यादा देखे जा रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि 20 से 40 साल की युवा महिलाओं में स्तन कैंसर की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं.

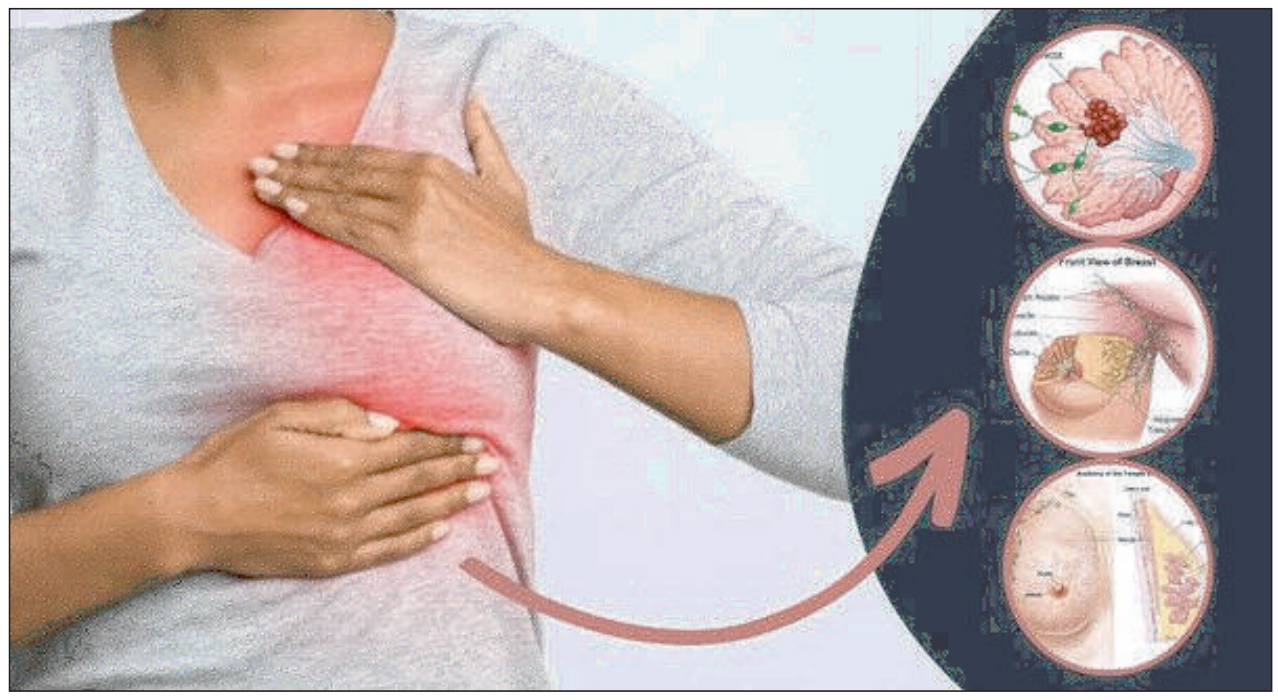

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, स्तन कैंसर दुनिया भर में महिलाओं को प्रभावित करने वाला सबसे आम प्रकार का कैंसर है. साल 2020 में 20 लाख से ज्यादा महिलाओं में स्तन कैंसर का पता चला और 6 लाख से अधिक मरीजों की जान चली गई. ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस (Breast Cancer Awareness) को लेकर हो रहे तमाम सम्मेलनों और रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं.

ब्रेस्ट कैंसर के क्या हैं शुरुआती लक्षण

स्तन कैंसर जागरूकता पर हाल ही में एक वेबिनार के दौरान फरीदाबाद स्थित अमृता हॉस्पिटल की मेडिकल ऑन्कोलॉजी की वरिष्ठ सलाहकार डॉ सफलता बाघमार ने कहा, 'स्तन कैंसर महिलाओं में पाए जाने वाले सबसे आम प्रकार के कैंसर के रूप में हेल्थ चार्ट में सबसे ऊपर है और हाल के दिनों में इसकी घटनाएं बढ़ी हैं. समय पर निदान और प्रभावी उपचार के लिए स्तन कैंसर के शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचानना बेहद जरूरी है. नई गांठें, स्तन की बनावट में बदलाव, त्वचा की अनियमितताएं, निपल से जुड़ी समस्याएं, निपल से खून आने जैसे बदलावों पर नजर रखना बेहद जरूरी है.'

डॉक्टर बाघमार ने कहा, 'इस बारे में खास बात यह भी याद रखनी चाहिए कि ये लक्षण जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, वे गैर-कैंसरजन्य बीमारियों या कंडिशन्स से भी जुड़े हो सकते हैं. इसलिए, जब संदेह हो, तो जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि यह आखिर क्या है और सही इलाज करवाना चाहिए. वैसे मन की शांति के लिए भी बेहतर है कि पेशेवर मार्गदर्शन लें.' (यह भी पढ़ें– स्तन कैंसर से बचने के लिए 40 की उम्र के बाद जरूर कराएं स्क्रीनिंग)

नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च की नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट के अनुसार, 'भारत में स्तन कैंसर महिलाओं में कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है. 2020 में, भारत में दो लाख से अधिक महिलाओं में स्तन कैंसर का इलाज होने का अनुमान लगाया गया था और अनुमान के अनुसार 76,000 से अधिक मौतें हुईं.' इसी रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में यह संख्या बढ़कर 2.3 लाख से अधिक होने की संभावना है.

गुरुग्राम के सीके बिड़ला अस्पताल में ऑन्कोलॉजी के प्रमुख सलाहकार और स्तन केंद्र के प्रमुख डॉ. रोहन खंडेलवाल ने बताया, 'भारत में, स्तन कैंसर की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेष रूप से 20 के दशक के अंत और 30 के दशक की शुरुआत में युवा भारतीय महिलाओं में.

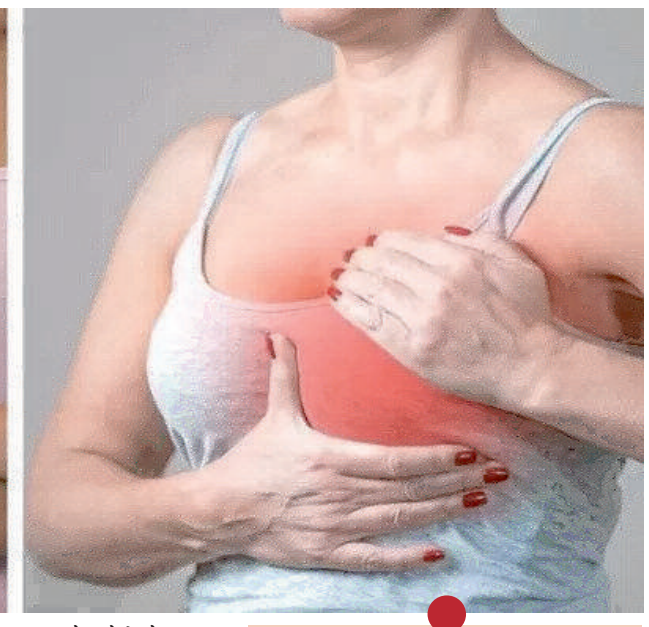

साल 2030 तक स्तन कैंसर दोगुना!

भारत में, स्तन कैंसर सर्वाइकल (cervical cancer) और ओरल कैविटी कैंसर (Oral Cavity Cancer) को पीछे छोड़ते हुए सबसे आम कैंसर और कैंसर से संबंधित मौतों का प्रमुख कारण बन गया है. अध्ययनों से संकेत मिलता है कि 2030 तक स्तन कैंसर के केस दोगुना होने की संभावना है. 20 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोग का जल्द से जल्द पता लगाने के लिए नियमित स्तन जांच कराने की सलाह दी जाती है."

डॉक्टरों के अनुसार, स्तन कैंसर के 60 प्रतिशत मामलों का निदान आमतौर पर एडवांस स्टेज में किया जाता है, जिससे इलाज की दर कम हो जाती है. फिर भी, नियमित जांच से इलाज की दर 80-90 प्रतिशत तक बढ़ सकती है.

स्तन कैंसर को लेकर कौन से टेस्ट कब करवाएं

कोच्चि के अमृता अस्पताल में रेडियोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मी आर ने कहा कि किशोरों और 20 से 30 वर्ष की आयु के लोगों के लिए, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग सबसे पहले करवाया जा सकता है, इसके बाद अगर आवश्यक हो तो मैमोग्राफी की जाती है. उन्होंने कहा, "30-40 वर्ष की महिलाएं मैमोग्राफी के साथ अल्ट्रासाउंड का विकल्प चुन सकती हैं. कंट्रास्ट-एन्हांस्ड मैमोग्राफी (सीईएम) प्रारंभिक पहचान के लिए एक एडवांस तकनीक है, खासतौर से तब जब मामला ज्यादा पेचीदा लग रहा हो. यह टेक्नोलॉजी एक प्रकार का प्रॉब्लम सॉल्वर है, और यहां तक कि कीमोथेरेपी प्रतिक्रिया मूल्यांकन के चरण और बाद में भी मदद करती है." (यह भी पढ़ें– सामान्य सूत्र प्रदूषण में लंग्स की गंदगी को करेंगे साफ)

उन्होंने कहा, "अगर मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और सीईएम में कुछ भी ऐसा लगे कि किसी नतीजे पर न पहुंचा जा रहा हो तो हमारे पास स्तन एमआरआई के साथ जाने का विकल्प है." डॉक्टरों ने अच्छा लाइफस्टाइल रूटीन अपनाने, हार्ट हेल्थ पर ध्यान देने, पौष्टिक खान-पान पर ध्यान देने और शारीरिक रूप से एक्टिव लाइफ स्टाइल रखने की सलाह दी।

भारत में, स्तन कैंसर सर्वाइकल (cervical cancer) और ओरल कैविटी कैंसर (Oral Cavity Cancer) को पीछे छोड़ते हुए सबसे आम कैंसर और कैंसर से संबंधित मौतों का प्रमुख कारण बन गया है. अध्ययनों से संकेत मिलता है कि 2030 तक स्तन कैंसर के केस दोगुना होने की संभावना है. 20 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोग का जल्द से जल्द पता लगाने के लिए नियमित स्तन जांच कराने की सलाह दी जाती है."

महिलाओं के लिए पीली किशमिश अधिक फायदेमंद या काली किशमिश? एक्सपर्ट ने कंफ्यूजन को किया दूर, बताए 5 चमत्कारी लाभ

किशमिश सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है. खासतौर पर महिलाओं के लिए. यदि आप किशमिश को भिगोकर खाते हैं तो इसका आपको दोगुना लाभ प्राप्त हो सकता है. हालांकि, इसका लाभ लेने के लिए महिलाएं अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज में आती हैं कि उन्हें पीली किशमिश खाना चाहिए या काली किशमिश. जी हां, एक्सपर्ट के मुताबिक, काली किशमिश महिलाओं के लिए अधिक फायदेमंद होती है. यह न सिर्फ प्रेग्नेंसी बल्कि यौन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भी असरदार मानी जाती है. यह इतनी कारगर है कि इसका पानी भी सेहत के लिए चमत्कार की तरह काम कर सकता है. आइए डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज दिल्ली की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. ज्योति यादव से जानते हैं काली किशमिश के चमत्कारी लाभ-

महिलाओं के लिए काली किशमिश के 5 चमत्कारी लाभ

यौन स्वास्थ्य बेहतर बनाए: एक्सपर्ट के मुताबिक, महिलाओं के लिए काली किशमिश अधिक फायदेमंद होती है. बता दें कि, काली किशमिश में अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में होता है, जो यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है. दरअसल, अमीनो एसिड संभावित रूप से गर्भधारण की संभावना को भी बढ़ा सकता है. इनमें एल-आर्जिनिन की मौजूदगी गर्भाशय और अंडाशय में ब्लड फ्लो को बढ़ा सकती है.

सर्दियों में सेहत के लिए रामबाण है मूंगफली

सर्दियों में सेहत के लिए रामबाण है मूंगफलीआगे देखें...

प्रजनन क्षमता बढ़ाए: महिलाओं को काली किशमिश अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए. दरअसल, प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए काली किशमिश का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है. इसके लिए इसे रातभर भीगने दें और अगले दिन छान लें. इसके बाद किशमिश को पीसकर उसका रस निकाल लीजिए. फिर आप इस मिश्रण को पी सकते हैं.

प्रेग्नेंसी में करें सेवन: काली किशमिश को गर्भावस्था के दौरान अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए. गर्भावस्था के दौरान काली किशमिश को पानी में भिगोने से कब्ज से प्रभावी रूप से राहत मिल सकती है. इसके अलावा काली किशमिश के पानी को डाइट में शामिल करने से गर्भवती महिलाओं को कई लाभ मिल सकते हैं. इसके अलावा, इसका नियमित सेवन एनीमिया को रोकने और हीमोग्लोबिन लेवल को बनाए रखने में मदद कर सकता है.

स्किन के लिए फायदेमंद: विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से युक्त काली किशमिश स्किन को पोषण देने का काम करती है. बता दें कि, इसके डिटॉक्सिफाइंग और एंटी-एजिंग गुण त्वचा को साफ, चमकदार और लंबे समय तक जवां बनाए रखने में मदद करते हैं. इसके अलावा, विटामिन सी मुंहासे को रोकने में भी मदद करता है. इसका लाभ लेने के लिए रोज एक कप पानी में 8-10 काली किशमिश भिगोकर इसका पानी खाली पेट पीना चाहिए.

इम्यूनिटी मजबूत करे: गर्भावस्था के दौरान इम्यून सिस्टम में बदलाव आते हैं. कई विटामिन और मिनरल से भरपूर काली किशमिश का पानी, इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकता है, जो सामान्य बीमारियों और इंफेक्शन से सुरक्षा प्रदान करता है. वहीं, काली किशमिश के पानी में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर लेवल को स्थिर बनाए रखने में योगदान देता है, जिससे इन कॉम्प्लीकेशन्स की संभावना कम हो जाती है.

40+ के बाद अपनी लाइफस्टाइल में एड करें ये हैल्दी डाइट, रहेंगी हमेशा फिट एंड फाइन

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है शरीर के अंग कमजोर होने लगते हैं. ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप कम उम्र से ही पोषक तत्वों से भरपूर चीजों का सेवन करें. साथ ही बढ़ती उम्र में भी उन सभी विटामिंस, मिनरल्स आदि को डाइट में शामिल करें, जो संपूर्ण सेहत के लिए जरूरी होते हैं. आपको बुजुर्गावस्था में बीमारियों से बचाए रखें. यह बात महिलाओं पर भी लागू होता है. खासकर, जब आपकी उम्र 40 पार हो रही हो तो आयरन, ओमेगा-3, प्रोटीन आदि से भरपूर चीजों का सेवन जरूर करें. अक्सर महिलाओं को पता नहीं होता है कि उन्हें 40 वर्ष की उम्र में कौन-कौन से जरूरी न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. आइए जानते हैं न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा से, जिन्होंने हाल ही में 40 वर्ष की उम्र की महिलाओं के लिए कुछ आवश्यक न्यूट्रिएंट्स के बारे में एक महत्वपूर्ण पोस्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. जानें, उनके अनुसार आपको इस उम्र के पड़ाव में क्या-क्या डाइट में शामिल करना चाहिए.

1. प्रोटीन

न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा का कहना है कि महिलाओं को 40 वर्ष की उम्र में प्रोटीन का सेवन जरूर करना चाहिए. इस उम्र में मेनोपॉज होने के पहले कई तरह के हॉर्मोनल बदलाव भी होते हैं. कई बार शरीर में फैट बढ़ जाता है, लीन मसल मास में कमी आ जाती है, जो बाद में उनके दीर्घायु को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि आप प्रोटीन का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें. यह लीन मसल्स के नुकसान को रोकने में मदद कर सकता है.

5 आदतों को डेली लाइफ में शामिल करें महिलाएं, खूबसूरती में आएगा निखार, बन जाएंगी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी

2. बी विटामिन

40 से अधिक की उम्र वाली महिलाओं के लिए बी-विटामिन श्रृंखला वाले विटामिंस भी बेहद जरूरी हैं. आप जो भी खाती हैं, उस भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने या बनाने के लिए आपके शरीर द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया में ये बी-विटामिन काफी मदद करते हैं. साथ ही लाल रक्त कोशिकाओं को भी बनाने में मदद करते हैं.

3.कैल्शियम

जैसे-जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, उनकी हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखता है. कैल्शियम के सेवन से ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम किया जा सकता है. यह एक ऐसी बीमारी है, जिसमें हड्डियां भंगुर (brittle) हो जाती हैं. कैल्शियम की जरूरत मांसपेशियों के संकुचन, नर्व, हार्ट के कामकाज और अन्य जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं जैसे शरीर के अन्य बुनियादी कार्यों के लिए भी होती है. यदि आप अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम शामिल नहीं करती हैं तो शरीर आपकी हड्डियों से कैल्शियम चुराने लगता है, जिससे हड्डियां धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं.

4. विटामिन डी

महिलाओं के लिए विटामिन डी भी बेहद जरूरी है. यह कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, इसलिए इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आप 40 की उम्र में आकर विटामिन डी भरपूर लें. साथ ही, विटामिन डी डायबिटीज, हृदय रोग सहित अन्य समस्याओं को कम करने में भी बेहद फायदेमंद होता है.

5. आयरन

क्या आप जानती हैं कि आपके शरीर को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है? यह एक ऐसा पदार्थ है, जो आपके लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है. 40 की उम्र ज्यादातर महिलाओं के लिए पेरिमेनोपॉज पीरियड का होता है. ऐसे में आयरन की कमी होने से आपको एनीमिया होने का जोखिम बढ़ सकता है. आयरन रिच डाइट आज से लेना शुरू कर दें.

6. ओमेगा-3 फैटी एसिड्स

माना जाता है कि ओमेगा-3 फैटी एसिड्स कॉग्निशन और हार्ट की सेहत में सुधार करते हैं. ये लाभकारी फैट शरीर के कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को भी सामान्य और नियंत्रित करते हैं. तो आप यदि 40 की हो चुकी हैं तो बेहद जरूरी है कि आप ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर फूड्स का सेवन करें.

महिलाएं अक्सर अपने खानपान का ध्यान नहीं रखती हैं. अगर आपकी उम्र 40 की हो गई है तो आपको कुछ जरूरी पोषक तत्वों को डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. खासकर ओमेगा-3, प्रोटीन आदि से भरपूर चीजों का सेवन जरूर करें. इससे आप हार्ट डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, खून की कमी जैसी समस्याओं से बची रह सकती हैं.

जेल में सीएम केजरीवाल का 8.5 किलो वजन कम होना गंभीर बीमारी का संकेत : संजय सिंह

सुषमा रानी

नईदिल्ली। 13 जुलाई आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्य सभा सदस्य संजय सिंह ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भाजपा का मकसद एक तरफ अरविंद केजरीवाल को जेल में रखकर उन्हें प्रताड़ति करना है और दूसरी तरफ वे उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो जाए या जेल में उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए। इसके लिए भाजपा एक गहरी साजिश रच रही है। जब 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, तब उनका वजन 70 किलोग्राम था, लेकिन आज उनका वजन 8.5 किलो घटकर 61.5 किलोग्राम रह गया है। 21 मार्च से अब तक अरविंद केजरीवाल का 8.5 किलो वजन घट गया है। इसका कारण किसी को नहीं पता है। इस तरह अकारण इतना वजन घटना किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। यह अरविंद केजरीवाल के परिवार और हम सभी के लिए बेहद चिंता का विषय है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का लगातार वजन घटने पर आम आदमी पार्टी ने गंभीर चिंता जताई है। ''आप'' के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद से अब तक उनका करीब 8.5 किलो वजन घट गया है। वजन का लगातार कम होना गंभीर बीमार का संकेत हो सकता है। 21 मार्च को गिरफ्तारी के समय उनका वजन 70 किलो था। अब यह घटकर 61.5 किलो रह गया है। इस बीच 5 बार सोने के दौरान सीएम का शुगर लेवल गिरकर 50 तक आ चुका है। अगर सोते समय अचानक शुगर गिरता है तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा और पीएम मोदी केजरीवाल को जेल में रखने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की साजिश रच रहे हैं। इसी साजिश के तहत इनकी ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर गैर कानूनी ढंग से स्टे लिया और बाद इन्होंने झूठे केस में सीबीआई से उन्हें गिरफ्तार करा दिया। ''आप'' को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई मामले में भी सीएम केजरीवाल को जल्द राहत मिलेगी।

संजय सिंह ने बताया कि जब से केजरीवाल जेल में हैं, लगभग पांच बार ऐसा हुआ है, जब रात में अचानक उनका शुगर लेवल गिरकर 50 से नीचे चला गया। हम सब जानते हैं कि शुगर लेवल का बढ़ना एक बार के लिए फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन अगर किसी व्यक्ति का शुगर लेवल सोते समय अचानक गिर रहा है तो वह कोमा में जा सकता है। यही स्थिति हमने आतिशी के पानी सत्याग्रह के समय देखी थी, जब उनका शुगर लेवल 41 पहुंच गया था, तब डॉक्टर्स ने सलाह दी कि वे कोमा में जा सकती हैं, उन्हें तुरंत एडमिट कराइए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 5 बार 50 से नीचे गया। रात में जेल के अंदर कौन सा डॉक्टर मौजूद रहता है? मैं 6 महीने जेल में रह कर आया हूं, अगर रात में आपको कोई समस्या हो जाए तो आप घंटी बजाते रहिए, बहुत मुश्किल से आपको ओपीडी ले जाया जाता है। यह सब क्यों किया जा रहा है?

उन्होंने कहा कि जैसे ईडी के ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी, तो ईडी ने बिना आदेश की कॉपी के हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली और एकमात्र घटना है। नियम कानून को ताक पर रखकर केजरीवाल की रिहाई पर स्टे ले लिया गया। लेकिन जब ऐसी पूरी संभावना थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी, तो उससे ठीक पहले सीबीआई ने एक झूठा केस केजरीवाल के खिलाफ बनाया ताकि ये लोग उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकें। यह अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ति तो कर ही रहे हैं, लेकिन भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की साजिश है कि केजरीवाल के साथ जेल में कोई दुर्घटना हो जाए। इसलिए कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पीएमएलए के तहत किसी को तभी जमानत मिल सकती है जब कोर्ट पूरी तरह यकीन हो जाए कि व्यक्ति पूरी तरह निर्दोष है। ईडी की कोर्ट ने भी केजरीवाल को निर्दोष मानते हुए जमानत दी। कोर्ट ने माना कि ईडी के अधिकारी दुर्भावना से केजरीवाल के खिलाफ केस बना रहे हैं। शुक्रवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी यह साफ लिखा है कि जांच का मतलब यह नहीं कि आप किसी को गिरफ्तार कर लें। कोर्ट ने ईडी की जांच पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। अपर बेंच से फैसला आएगा और हमें उम्मीद है कि आज जिस तरह से पीएमएलए और ईडी-सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केवल विरोधियों को प्रताड़ति करने के लिए किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की अपर बेंच उस पर रोक लगाएगी। आज अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की स्थिति पूरे देश को मालूम होनी चाहिए कि अगर उन्हें जल्द ही बाहर लाकर सही इलाज नहीं किया गया तो जेल में उनके साथ कोई भी गंभीर घटना घट सकती है। अगर सोते समय इसी तरह से उनका शुगर लेवल गिर जा रहा है तो उनके साथ कोई भी घटना हो सकती है और वे कोमा में भी जा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई के मामले में भी उन्हें जल्द राहत मिलेगी। अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ भी हमारे साथ कर रहे हैं हम उसका मिलकर जवाब देंगे।

दिल्ली मूनक नहर तटबंध दुरूस्त, वाटर ट्रीटमेंट शुरू

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। बुद्धवार रात दिल्ली की प्यास. बुझाने वाली मूनक नहर का 35 फिट तटबंध टूटने से बवाना समेत आस-पास की दर्जनभर कॉलोनियों में 5 फुट तक पानी घरो में घुस गया था। तमाम गली, सडक सब जगह 4-5 फुट पानी खडा हो गया था। इससे इलाके में जन-जीवन पानी पानी होने से पैदल की जगह नौका विहार का दृश्य बन गया था। इसके अलावा हैदर पुर जल संयत्र तक बिन पानी के बंद करने पड गए थे। रोहिणी, बुद्ध विहार, नांगलोई, मंगोल पुरी, सुलतान पुरी, सेंट्रल दिल्ली समेत द्वारका तक में पानी की सप्लाई ठप हो गई थी। दिल्ली में जलापूर्ति को लेकर इन कालोनियों में हाहाकार मच गया था। इस बावत दिल्ली जल मंत्री आतिशी के मुताबिक गुरूवार सुबह से शुक्रवार तक लगातार मूनक नहर की मरम्मत का कार्य इमर्जेंसी के बतौर दिन-रात चलता रहा। शुक्रवार दोपहर को रिपेयर वर्क पूरा हो गया है। नहर के तटबंध को सीमेंट से मजबूत किया जा रहा है। आतिशी के मुताबिक 10:30 बजे हरियाणा करनाल से नहर में पानी को छोड भी दिया गया है। 1:30- 2:00 बजे तक पानी दिल्ली पहुंच गया है। उसके बाद 4:00 बजे द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो गया है। रात तक द्वारका में शुद्ध जल की सप्लाई जारी हो जाएगी। इसके अलावा तमाम प्रभावित क्षेत्रों में भी पानी की सप्लाई जारी है। मूनक नहर को पाटने के लिए करीब 100 से अधिक डंपर मिट्टी डाली गई है। उधर हरियाणा सिंचाई विभाग के अधिकारी के मुताबिक मूनक नहर का तटबंध टूटने का कारण जानने के लिए विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी जल्द अपना कार्य शुरू कर देगी। कमेटी को जल्द से जल्द अपनी जांच रिपोर्ट देने को कहा है। अधिकारियो के मुताबिक नहर का तटबंध टूटना थोडा अप्रत्याशित लग रहा है।

सब्जियों के रेट सरकार गिराने वाले, पर कोई फर्क नहीं अलबत्ता

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी, नईदिल्ली। साल 1993 में दिल्ली की भाजपा सरकार में प्याज के रेट 40 रूपये किलो हो गए थे। तब राजधानी दिल्ली में भूचाल आ गया था। प्याज के बडी कीमत से दिल्ली वाले इतने नाराज हुए कि उन्होने 1993 के दिल्ली राज्य की सुषमा स्वराज की सरकार को उखाड फेंका था। लेकिन आज दिल्ली में आमआदमी की सरकार के होते हुए सब्जियों की बढती कीमती पर कोई लगाम नहीं लगा पाई है। अब आलम ये है कि टमाटर की बडी हुई कीमत से टमाटल रंग बदलने लगा है। इस वक्त टमाटर का रेट 50-60 रूपये किलो के भाव पहुंच गया है। देखने में आ रहा है कि टमाटर की कीमत रोज-ब-रोज अपने कीर्तिमान बना रही है। वहीं लहसुन ने अपनी गांठ मजबूत कर ली है वह भी 400 रूपये किलो के भाव खा रहा है। लहसुन का भाव भी पिछले 1 साल से इसी कीमत पर टिक गया है। इसके अलावा अदरक भी भाव खा रही है। वह भी 300 रूपये किलो के भाव में पंजे लडा रही है। इसी क्रम में हरा धनिया भी 250 रूपये किलो के भाव में बिक रहा है। सब्जियों के इतने भाव चढ जाने के बावजूद दिल्ली सरकार का सब्जियों के लगातार बढते रेट पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। हर चीज के मुंह मांगे दामों ने जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। ताज्जुब तो इस बात का है कि दिल्ली सरकार सब्जियों की आसमान छूती कीमतों के बाद भी संबधित विभाग मंत्रालय स्नात बैठे है। अब हालत ये है कि आम जनता दो पाटो के बीच पिस - पिस कर चटनी बन रही है।

वहीं दामोदर की दिन-ब- दिन चढती कीमतो से दुखी लोग अब दाल रोटी खाओ प्रभु के गुन गाओ के गाने गाने तक पर मुंह सिल लिया है।

मसूर, उडद, चना, अरहर, मूंग की दाल एक बार 150 रूपये के पार जाने को तैयार है। आम जनता चटनी से भी रोटी खाने को भी मोहताज हो गई है। खाने पीने की हर चीज के दाम आगे-आगे दौड रहे है और जनता पीछे-पीछे दौड लगा रही है। मीडिया सिर्फ आम जनता को उसके हाल पर छोड सिर्फ अनंत अंबानी और राधिका की 3700 की शाही शादी को दिखाकर चटखारे ले रहा है। लगता है आम जनता की हालत और जरूरत से बेखबर चिढाने की मुद्रा में आ गया है। हालत ये ही कि सत्ता पक्ष और विपक्ष तक अंनत अंबानी और राधिका की शाही शादी का.लुत्फ लेने में मग्न है। उन्हें आम जनता के सरोकार से कोई लेना देना नहीं है।

दिल्ली में सड़क पर भरे पानी में रखा पैर और हो गई महिला की मौत, PWD की लापरवाही आई सामने

परिवहन विशेष न्यूज

यमुना विहार में वजीराबाद रोड किनारे सी-ब्लॉक की सर्विस रोड पर यह हादसा हुआ है। महिला अस्पताल में इलाज के लिए जा रही थीं। पुलिस ने लापरवाही से मौत के मामले में जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों का आरोप है कि नाला और स्ट्रीट लाइट के खंभे पीडब्ल्यूडी के हैं। इस विभाग की लापरवाही से हादसा हुआ है।

पूर्वी दिल्ली। यमुना विहार में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। सड़क पर भरे वर्षा जल में पैर रखते ही महिला की करंट लगने से मौत हो गई। आरोप है कि घटनास्थल के पास लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे से बाहर निकल रही तार से करंट पानी में पहुंचने के कारण हादसा हुआ।

मृतका की पहचान पूनम (34) के रूप में हुई है, वह परिवार के साथ गामड़ी एक्सटेंशन गली नंबर-19 में रहती थीं। वह किडनी में संक्रमण की जांच कराने के लिए एक डाइग्नोस्टिक सेंटर पर जा रही थीं। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया है। लापरवाही से मौत के आरोप में प्राथमिकी कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

बेटे की मानसिक तबीयत है खराब

पूनम के परिवार में पति रविंद्र कुमार, 14 वर्षीय बेटा अर्णब है। उनके पति घर के नीचे परचून की दुकान चलाते हैं। जेठ जसवंत और देवर गुड्डू का परिवार उनके साथ मकान में अलग तल पर रहता है। बेटा अर्णब मानसिक रूप से कमजोर है, वह पिछले 10 दिन से सीने में संक्रमण होने पर बुखार के चलते नई दिल्ली के अरुण आसिफ अली अस्पताल में भर्ती था, शनिवार को ही उसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया।

पूनम भी जा रही थीं अस्पताल

पूनम भी बीमार थीं, उनका भी अरुण आसिफ अली अस्पताल में उपचार चल रहा था। उनको गर्भाश्य में गांठ व पथरी के कारण किडनी में संक्रमण होने की आशंका थी। वह शनिवार सुबह अस्पताल से ही सीधे जांच कराने के लिए यमुना विहार आई थीं।

बस से वजीराबाद रोड पर उतर कर वह यमुना विहार सी-ब्लॉक की सर्विस रोड पर पहुंचीं, वहां तड़के हुई वर्षा का पानी भरा हुआ था। वह सर्विस रोड के किनारे नाले पर बने फुटपाथ से एक निजी डाइग्नोस्टिक सेंटर जा रही थीं। जहां पर फुटपाथ खत्म हुआ, वहां से उन्हें पानी के बीच से जाना था।

देखने वालों ने क्या बताया

चाय की दुकान चला रहे प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद साजिद ने बताया कि सुबह करीब 7:30 बजे हादसा हुआ। फुटपाथ से नीचे पानी में पैर रखते ही महिला मुंह के बल सड़क पर गिर गई। इतने में पास में मोरल नर्सिंग होम का एक गार्ड आया, उन्होंने ग्लव्ज और रबड़ के जूते पहनने के बाद महिला को बाहर निकाला। नर्सिंग होम में महिला की जांच की तो वह मृत थीं।

हादसे की भनक लगते ही इस सर्विस रोड पर मशीन लगाकर पानी साफ करा दिया। पुलिस का कहना है कि सर्विस रोड पर घटनास्थल के पास स्ट्रीट लाइट के खंभे के पैनल का दरवाजा खुला था, वहां से तार निकल रही थी। इसी तार से सड़क पर भरे वर्षा के पानी में करंट पहुंचा। आसपास के लोगों का आरोप है कि नाला और स्ट्रीट लाइट के खंभे पीडब्ल्यूडी के हैं। इस विभाग की लापरवाही से हादसा हुआ है। इस बार नाला साफ नहीं कराया है, इस कारण जल भराव हो रहा है। खंभों का रखरखाव भी ठीक से नहीं करते।

गार्ड को लगा करंट, तब जूते और ग्लव्ज पहने

महिला को निकालने वाले नर्सिंग होम के गार्ड अतुल ने बताया कि महिला के गिरते ही वह उसे बचाने दौड़े थे, लेकिन पानी में पैर पड़ते ही करंट का झटका लगा। फिर वह नर्सिंग होम से रबड़ के ग्लव्ज और जूते पहन कर आए थे। महिला को पानी से बाहर निकालने के बाद सीपीआर भी दिया था, लेकिन शरीर में हरकत नहीं थी। चेहरे या शरीर के अन्य किसी हिस्से पर गिरने से कोई चोट नहीं लगी थी। किसी ने महिला को पानी से बाहर निकालने के दौरान वीडियो बनाया था, जो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

घटना के करीब तीन घंटे बाद मृतका के भाई मनीष और मनोज अपने रिश्तेदारों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मनीष ने बताया कि उनको भजनपुरा थाना पुलिस से सुबह 11 बजे हादसे की जानकारी मिली। उनका आरोप है कि पीडब्ल्यूडी की लापरवाही ने उनकी बहन को उनसे छीन लगया। उनकी मांग है कि इस मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कर उनको न्याय दिलाया जाए।

चरम मौसमी घटनाएं बिगाड़ रहीं शहर की सूरत, दिल्ली के बुनियादी ढांचे को जलवायु सुरक्षा की जरूरत

अत्यधिक गर्मी व सर्दी भीषण लू और भारी वर्षा की मार झेल रही दिल्ली सहित अन्य शहरों को जलवायु परिवर्तन से सुरक्षित बनाना जरूरी हो गया है। सीईईडब्ल्यू के विश्लेषण के अनुसार बदलती जलवायु के बीच शहरों का भविष्य कैसा हो सकता है इसकी लगातार झलक देखी जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म हवा नमी को ज्यादा धारण कर रही है।

नई दिल्ली। चरम मौसमी घटनाओं के चलते दिल्ली एवं अन्य शहरों की बदहाली लगातार देखने को मिल रही है। कभी भीषण लू तो कभी शीत लहर, कभी भारी वर्षा और बाढ़... से ज्यादातर शहरों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) का विश्लेषण बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हमने शहरों के बुनियादी ढांचे की कोई क्लाइमेट प्रूफिंग नहीं की है। मतलब ये कि उसे जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाना होगा।

सीईईडब्ल्यू के विश्लेषण के अनुसार, पिछले तीन दशकों यानी 1982-2011 की तुलना में पिछले एक दशक (2012-2022) में देश के 64 प्रतिशत से अधिक तहसीलों में भारी वर्षा वाले दिनों की संख्या में बढ़ोत्तरी देखी गई है। भारी वर्षा की घटनाओं में वृद्धि इस बात की एक झलक है कि बदलती जलवायु में हमारे शहरों का क्या भविष्य हो सकता है। दिल्ली जैसे शहरों को लगातार भीषण लू के बाद कम समय में भीषण वर्षा का सामना करना पड़ रहा है।

जलवायु परिवर्तन से क्या हुआ बदलाव

जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ है, गर्म हवा की नमी को धारण करने की क्षमता भी बढ़ी है, जिससे वर्षा वाले दिनों की संख्या घटी है। ऐसे में, जब कभी वर्षा होती है तो बहुत ज्यादा भारी बारिश होती है। इसके अलावा एक ही जिले के भीतर मानसूनी वर्षा के बहुत अलग पैटर्न भी उभर रहे हैं।

दिल्ली में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश

उदाहरण के लिए एक जून से 10 जुलाई तक, पश्चिम दिल्ली में सामान्य से 99 प्रतिशत कम वर्षा हुई, जबकि उत्तर पश्चिम दिल्ली के समीपवर्ती जिले में 122 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई। वर्षा का यह असमान वितरण बुनियादी ढांचे और समुदायों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यह हमारे बुनियादी ढांचे को जलवायु-परिवर्तन से सुरक्षित बनाने (क्लाइमेट-प्रूफिंग) की जरूरत को रेखांकित करता है।

दिल्ली करती है भीषण लू और बारिश का सामना

सीईईडब्ल्यू के सीनियर लीड विश्वास चितले ने बताया कि दिल्ली जैसे शहरों को पहले भीषण एवं लंबे समय तक चलने वाली लू और फिर कम समय में भीषण वर्षा, हवा की नमी धारण करने बढ़ी हुई क्षमता का सामना करना पड़ता है। वर्षा का ऐसा असंतुलित वितरण बुनियादी ढांचे और लोगों पर गंभीर प्रभाव डालता है। यह स्थिति हमारे बुनियादी ढांचे की क्लाइमेट-प्रूफिंग की अति महत्वपूर्ण जरूरत को रेखांकित करती है।

13 जुलाई को देश के कई हिस्सों बारिश का था अलर्ट

चितले के अनुसार, मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक देश के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किए। इसमें उत्तर-पूर्वी राज्य एवं सिंधु-गंगा मैदान के राज्य जैसे बिहार और पश्चिमी तट के शहर जैसे मुंबई भी शामिल हैं। हाल ही में, दिल्ली में 28 जून को एक ही दिन में जितनी वर्षा हुई, वह जून की सामान्य वर्षा की लगभग दोगुनी थी। वहीं, सीईईडब्ल्यू के सीनियर प्रोग्राम लीड नितिन बस्सी कहते हैं, स्थानीय स्तर पर बहुत भारी वर्षा (24 घंटों में 115 से 204 मिमी से ज्यादा) से आ सकने वाली वाली शहरी बाढ़ का प्रभाव घटाने के लिए, दिल्ली को जलवायु जोखिम आधारित नियोजन (प्लानिंग) से लाभ होगा।

सफदरजंग अस्पताल में आयोजित हुआ सहायक प्रौद्योगिकी और अभिगम्यता पर कार्यक्रम

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सफदरजंग अस्पताल के फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन (पीएमआर) विभाग ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के सहयोग से सहायक प्रौद्योगिकी और सुगमता पर केंद्रित सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) सह कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 55 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और आकर्षक पैनल चर्चाएँ हुईं।

सफदरजंग अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वंदना तलवार ने सीएमई का उद्घाटन करते हुए इस बात पर जोर दिया, ₹विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण घटक है। यह सीएमई इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में ज्ञान और अभ्यास को आगे बढ़ाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।₹ उन्होंने आगे कहा कि सहायक प्रौद्योगिकी का प्रभाव गहरा है। यह निर्भरता और स्वतंत्रता, बहिष्कार और समावेश, सीमित संभावनाओं और समाज में पूर्ण भागीदारी के बीच का अंतर हो सकता है।

आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रविंदर सिंह, जिन्होंने कहा, "सहायक प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रही प्रगति ने पहुंच में सुधार के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान किए हैं। आईसीएमआर में हमारा ध्यान ऐसे शोध का समर्थन करना है जो इन नवाचारों को रोगियों के लिए व्यावहारिक, जीवन-परिवर्तनकारी समाधानों में बदल सके।"

सफदरजंग अस्पताल के पीएमआर विभाग के प्रमुख डॉ. अजय गुप्ता ने संस्थान की भूमिका पर प्रकाश डाला: "पुनर्वास चिकित्सा में अग्रणी के रूप में, हम सफदरजंग अस्पताल में अपने रोगी देखभाल प्रोटोकॉल में अत्याधुनिक सहायक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के लिए समर्पित हैं। यह सीएमई यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है कि हमारे चिकित्सा पेशेवर इन विकासों में सबसे आगे रहें।"

डॉ. सुमन बधाल ने कहा, "आईसीएमआर, एम्स, एनआईएचएफडब्ल्यू, एएलआईएमसीओ और पीएमआर विशेषज्ञों से आए प्रतिनिधियों से आज हमने जो उत्साह और जुड़ाव देखा है, वह स्वास्थ्य सेवा में सहायक प्रौद्योगिकी के महत्व की बढ़ती मान्यता को रेखांकित करता है। तकनीकी प्रगति के माध्यम से रोगी परिणामों को बेहतर बनाने में इतनी रुचि देखना उत्साहजनक है।" सीएमई ने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को सहायक प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति पर चर्चा करने और विभिन्न विकलांगताओं वाले रोगियों के लिए पहुँच बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान किया। पैनल चर्चाओं को विशेष रूप से अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जिसमें उपस्थित लोगों की सक्रिय भागीदारी थी।

एक प्रतिनिधि ने टिप्पणी की, ₹पैनल चर्चाओं के दौरान साझा की गई अंतर्दृष्टि अमूल्य रही है। यह स्पष्ट है कि अंतःविषय सहयोग सहायक प्रौद्योगिकी और पहुँच में सार्थक प्रगति करने की कुंजी है।"

यह कार्यक्रम सफदरजंग अस्पताल की चिकित्सा शिक्षा और रोगी देखभाल, विशेष रूप से पुनर्वास चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे आगे रहने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। आयोजकों ने इस तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हुए इसे एक वार्षिक कार्यक्रम बनाने का इरादा व्यक्त किया।

केजरीवाल की वजह से दिल्ली वाले नारकीय जीवन जीने को मजबूर: गजेंद्र यादव

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। गर्मी के मौसम से लगातार दिल्ली में हो रही पानी की किल्लत और अब बारिश के कारण से चौतरफा जाम साथ ही साथ जल भराव की समस्या से दिल्ली के लोग नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है जिसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके विधायक हैं यह कहना है प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष गजेंद्र यादव का

दक्षिण दिल्ली लोकसभा के अंबेडकर नगर विधानसभा में विधायक अजय दत्त के खिलाफ स्थानीय लोगों ने गजेंद्र यादव के नेतृत्व में एक विशाल प्रदर्शन किया जिसमें स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानियों के लिए वहां सभी को अवगत कराया भारी पुलिस बल के बीच लोगों ने खूब जमकर नारेबाजी करी प्रदर्शन में आए हुए महिला बुजुर्ग युवा सभी का कहना था कि उनके घरों में सिविर लाइन का पानी मिक्स होकर आता है जो पीने लायक नहीं पिछले 10 वर्षों में विधायक ने सीवर पानी और सड़क पर बिल्कुल भी काम नहीं किया और तो और जब लोग शिकायत लेकर विधायक के पास जाते हैं तो विधायक उनको अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में आने के लिए दबाव डालते हैं

प्रदर्शन का नेतृत्व खानपुर के निगम पार्षद ममता यादव भाजपा नेता हरीश यादव ने किया भाजपा प्रदर्शन में समीर बावरिया, सुभाष नागर, विजय बागड़ी, मंडल अध्यक्ष नवीन गुप्ता, ऋषिपाल, तरुण प्रकाश, विनोद बॉक्सर, राम कुमार यादव, शकील एहमद, प्रदीप कनोजिया, तुलसी नावरिया, रोशनी बिष्ट, सुरेन्द्र चौधरी, युवा नेता सौरभ कुड़िया, पंकज कुड़िया ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।

गाजियाबाद में बनेगा पहला बायो डायवर्सिटी पार्क मिलेंगी ये सुविधाएं; दिल्ली NCR के लोगों की भी आने की संभावना

परिवहन विशेष न्यूज

शहरवासियों के लिए खुशखबरी है। नगर निगम 17 करोड़ की लागत से 65 एकड़ भूमि पर जिले में पहला बायोडायवर्सिटी पार्क बनाएगा। शासन ने प्रोजेक्ट की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। जल्द शासनादेश जारी होगा। इसके बाद महामाया स्टेडियम के पीछे सिद्धार्थ विहार में पार्क बनाने का काम शुरू होगा। नगर आयुक्त ने बताया कि बायो डायवर्सिटी पार्क को बेहतरीन पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा।

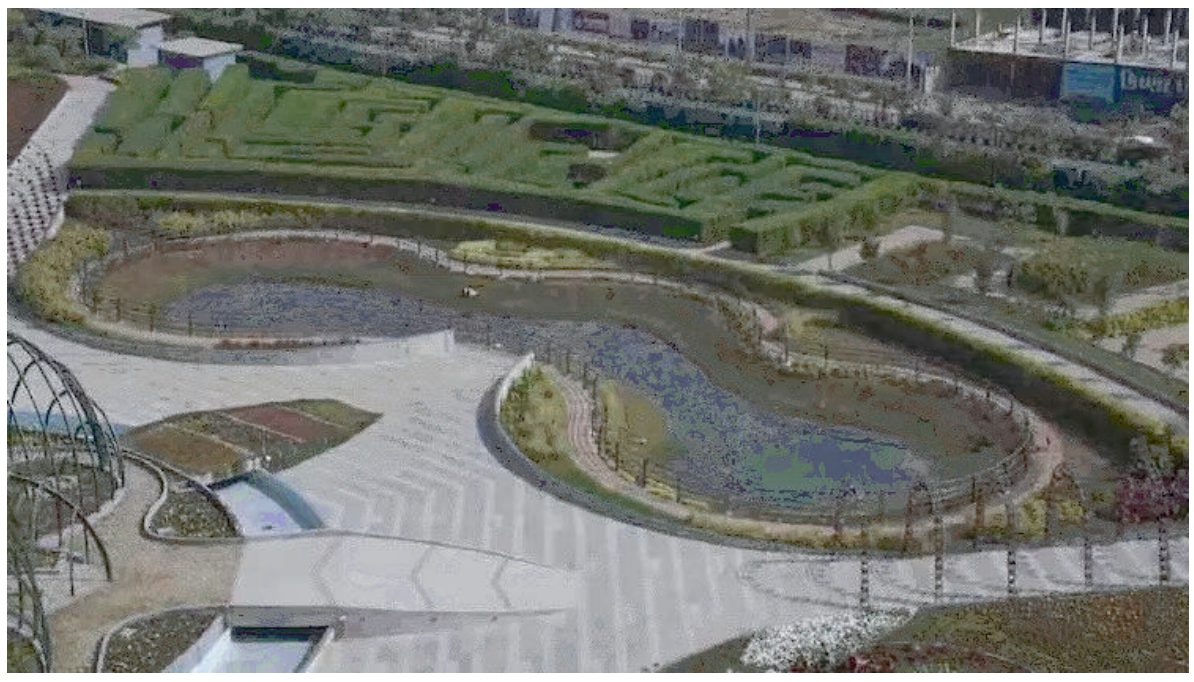

गाजियाबाद। शहरवासियों के लिए खुशखबरी है। नगर निगम 17 करोड़ की लागत से 65 एकड़ भूमि पर जिले में पहला बायोडायवर्सिटी पार्क बनाएगा। शासन ने प्रोजेक्ट की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। जल्द शासनादेश जारी होगा।

इसके बाद महामाया स्टेडियम के पीछे सिद्धार्थ विहार में बायो डायवर्सिटी पार्क बनाने का काम शुरू होगा। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि बायो डायवर्सिटी पार्क को बेहतरीन पिकनिक स्पाट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह प्रदूषण को कम करने में भी मददगार साबित होगा, क्योंकि यह पार्क नमो भारत ट्रेन के गाजियाबाद स्टेशन के नजदीक बनाया जाएगा।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ व दिल्ली के लोगों का आना भी संभावित

ऐसे में यहां पर न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ व दिल्ली के लोगों का आना भी संभावित है। उन्होंने बताया कि पार्क के अंदर बटरफ्लाई गार्डन, फव्वारे, सोलर लाइट, पाथ-वे, साइकिल ट्रैक, वाच टावर, नर्सरी, प्ले ग्राउंड, फाउंटेन, लोटस पांड, फिश पांड, फॉरेस्ट रेस्टोरेंट, गार्डन कैफे के साथ ही यहां रिसर्च सेंटर भी होगा, जहां जैव विविधता से जुड़े शोध होंगे। हर वर्ग के लोग यहां आकर अपना मनोरंजन कर सकेंगे।

बायो डायवर्सिटी पार्क में बनाए जाएंगे सेल्फी प्वाइंट

छात्रों को यहां वनस्पति विज्ञान की जानकारी मिलेगी। यहां 33 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता का एसटीपी लगेगा, जिससे नाले का पानी शोधित कर जलाशयों में भरा जाएगा। बायो डायवर्सिटी पार्क शहर की सुंदरता को बढ़ाएगा। बायो डायवर्सिटी पार्क में सेल्फी प्वाइंट भी बनाए जाएंगे। बच्चे, बूढ़े, जवान हर उम्र के लोग यहां मनोरंजन के लिए आ सकेंगे।

दरअसल, महामाया स्टेडियम के पीछे जमीन पर कूड़ा इकट्ठा होता था, जिसमें अक्सर आग लगा दी जाती थी। यहां शहर के कई हिस्सों से आकर गंदा पानी भी इकट्ठा होता है, जिस कारण यह प्रदूषण की बड़ी वजह बनता जा रहा है।

मल्टीलेवल पार्किंग और मेट्रो स्टेशन से भी होगी कनेक्टिविटी

पास में ही साईं उपवन और ईको पार्क को भी इससे नुकसान हो रहा था। इसीलिए बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने का निर्णय लिया गया। यहां जाने के लिए जीटी रोड के साथ मल्टीलेवल पार्किंग और मेट्रो स्टेशन से भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। न्यू लिंक रोड फ्लाईओवर के नीचे वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।

सुबह जमकर बरसे बादल, दोपहर में रही उमस भरी गर्मी; जानें आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

गाजियाबाद में शनिवार को हवा अधिकतम छह किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चली। वातावरण में आर्द्रता 68 प्रतिशत दर्ज की गई। अगले दो दिन आसमान में बादल रहने के साथ वर्षा होने का अनुमान है। तापमान में बढोतरी हो सकती है। रविवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने के और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं।

गाजियाबाद। रात से मंडरा रहे बादल शनिवार की सुबह शहर के विभिन्न इलाकों में जमकर बरसे। लेकिन दोपहर में तेज धूप रहने से उमस भरी गर्मी महसूस हुई। शाम को फिर से बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। वर्षा होने के आसार हैं।

कई दिन से लगातार बादल छाए रहने के साथ बीच-बीच में बूंदाबांदी भी हो रही थी। लेकिन बीच-बीच में धूप निकलने से काफी ज्यादा उमस भरी गर्मी बनी हुई थी। शुक्रवार को भी आसमान में बादल मंडरा रहे थे। शनिवार तड़के बादल घिर आए और तेज वर्षा शुरू हो गई। दोपहर में फिर से धूप निकली तो काफी ज्यादा गर्मी रही। शाम को शहर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

वातावरण में आर्द्रता 68 प्रतिशत दर्ज

हवा अधिकतम छह किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चली। वातावरण में आर्द्रता 68 प्रतिशत दर्ज की गई। अगले दो दिन आसमान में बादल रहने के साथ वर्षा होने का अनुमान है। तापमान में बढोतरी हो सकती है। रविवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने के और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। हवा अधिकतम आठ किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वातावरण में आर्द्रता 64 प्रतिशत रह सकती है।

शादी समारोह में बदमाशों ने दूल्हे के भाई से लूटी सोने की चेन, पुलिस आई पर कहा- हम तो डीजे बंद कराने आए

सिकंद्राबाद के गांव मुरादाबाद निवासी भारत कुमार के चचेरे भाई की बृहस्पतिवार को महरौली में शादी थी। रात नौ बजकर 50 मिनट पर वह जेपीएस गार्डन के बाहर खड़े हुए थे। इसी बीच हापुड़ की तरफ से बाइक पर दो युवक हेलमेट लगाए हुए आए और उनके गले से करीब दो तोले सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस को कॉल कर केस दर्ज कराया।

गाजियाबाद। वेब सिटी थानाक्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे के चचेरे भाई से चेन लूट ली। पीड़ित का कहना है कि लूट के करीब दो मिनट बाद में मौके पर पुलिस की एक गाड़ी आई थी। पुलिसकर्मियों को घटना की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि डायल 112 पर कॉल करें। हम तो डीजे बंद कराने आए हैं। पीड़ित ने इसके बाद डायल 112 पर पुलिस को घटना की सूचना दी। सिकंद्राबाद के गांव मुरादाबाद निवासी भारत कुमार के चचेरे भाई की बृहस्पतिवार को महरौली में शादी थी। रात नौ बजकर 50 मिनट पर वह जेपीएस गार्डन के बाहर खड़े हुए थे। इसी बीच हापुड़ की तरफ से बाइक पर दो युवक हेलमेट लगाए हुए आए और उनके गले से करीब दो तोले सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। पीड़ित पुलिस को फोन करते इसी बीच पुलिस की एक गाड़ी वहां आ गई।

अज्ञात वाहन सवार बदमाशों पर केस दर्ज

उन्होंने पुलिसकर्मियों को लूट की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि वह तो रात 10 बजे के बाद डीजे बंद करने के लिए सूचित करने आए हैं। पुलिस को बुलाने के लिए वह डायल 112 मिलाएं। भारत कुमार के मुताबिक उन्होंने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। उनकी सूचना पर पुलिस मौके पर आई और जांच की इसके बाद उन्होंने लिखित शिकायत दी। पीड़ित की शिकायत पर वेव सिटी थाने में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित का कहना है कि मौके पर किसी अन्य काम से आए पुलिसकर्मी यदि प्रयास करते तो हो सकता है बदमाश पकड़े जाते।

नोएडा में घर बनाना हुआ महंगा, आवासीय से लेकर ग्रुप हाउसिंग सोसायटी तक के भूखंडों के इतने बढ़ गए दाम

नोएडा में घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो आपको अपनी जेब और ढीली करनी पड़ सकती है। लखनऊ में आयोजित हुई Noida Authority की 214वीं बैठक में नोएडा में आवासीय औद्योगिक ग्रुप हाउसिंग और संस्थागत संपत्तियों की आवंटन दरों में 6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। हालांकि ध्यान देने योग्य बात है कि कॉर्पोरेट ऑफिस की संपत्तियों में कोई बढ़त नहीं हुई है।

नोएडा। नोएडा में आवासीय, औद्योगिक, ग्रुप हाउसिंग और संस्थागत संपत्तियों की आवंटन दरों में 6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। संस्थागत उपयोग के अंतर्गत कॉर्पोरेट ऑफिस और व्यावसायिक संपत्तियों की दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

यह निर्णय शुक्रवार को लखनऊ में हुई नोएडा प्राधिकरण की 214 वीं बोर्ड बैठक में लिया गया। लखनऊ स्थित पिकअप भवन में आयोजित बोर्ड बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने की।

इसमें नोएडा प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम, ग्रेनो प्राधिकरण सीईओ रवि कुमार एनजी, यमुना प्राधिकरण सीईओ अरूणवीर सिंह समेत बोर्ड के अन्य सदस्य शामिल रहे।

नोएडा प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम ने बताया कि आवासीय भूखंड की श्रेणी ए, बी औ सी में करीब 17500 वर्ग मीटर जमीन के तहत करीब 50 भूखंड खाली पड़े हुए हैं। अब नए रेट लागू होने पर इन भूखंडों को प्राधिकरण बेचेगा। औद्योगिक व संस्थागत संपत्तियों के हिसाब से शहर को तीन वर्गों में बांटा हुआ है।

आवासीय दरों में 6 प्रतिशत का इजाफा

जहां तक आवासीय भूखंडों का सवाल है, शहर को ए प्लस से ई तक छह श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जबकि ए प्लस (सेक्टर 14 ए, 15 ए, और 44 ए और बी) में भूमि आवंटन दर सबसे अधिक है और ई में सबसे कम है।

प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ए प्लस से ई श्रेणी के सेक्टर के लिए प्रचलित दरों में 6 प्रतिशत की वृद्धि की है। हालांकि श्रेणी ए प्लस आवासीय भूखंडों की दर 1.75 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर पर ही रहेगी।

ए श्रेणी के सेक्टरों (14, 17, 19, 30, 35, 36, 39, 44, 47, 50, 51, 52, 93, 93ए और 93बी) में भूखंडों की दर 1.18 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़ा दी गई है। 1.25 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर। बी, सी, डी और ई के लिए दरें 82,420 रुपये से 45,380 रुपये से बढ़ाकर 87,370 रुपये से 48,110 रुपये तक कर दी गई हैं।

आवासीय भूखंडों के लिए प्राधिकरण ने पाया कि ई-नीलामी में बोलियां अधिकतर रिजर्व प्राइज से 30 प्रतिश अधिक होती हैं। जिसमें उपलब्ध भूखंड की तुलना में आवेदनों की संख्या काफी अधिक होती है।

आवासीय भूखंडों की नई आवंटन दरें

श्रेणी	पुरानी दरें	नई दरें
ए प्लस	175000	175000
बी	82420	87370
सी	60020	63620
डी	50170	53180
ई	45380	48110

(नोट : यह दरें रुपये प्रति वर्ग मीटर में हैं)

6 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद ग्रुप हाउसिंग की दर

ग्रुप हाउसिंग संपत्तियों को भी ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाता है, जिसमें भूखंड के स्थान और बाजार मूल्य के आधार पर आवंटन की बोली लगाई जाती है। इस उद्देश्य के लिए, शहर को पांच में वर्गों में वर्गीकृत किया गया है- ए से ई तक।

जबकि प्रचलित दरें 1.03 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर से 65,250 प्रति वर्गमीटर तक हैं, उन्हें बढ़ाकर 1.09 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर से 69,170 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है।

वर्ग मीटर श्रमिक कुंज और ईडब्ल्यूएस आवासीय भवनों की दरें 10,140 रुपये प्रति वर्गमीटर पर अपरिवर्तित रहेंगी।

फेस वन, फेज टू और फेस तीन के अलावा आईटी-आईटीईएस एवं डाटा सेंटर उपयोग की परिसंपत्तियों की आवंटन दरों में भी 6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। बीते सालों में व्यावसायिक संपत्तियों के बेहद कम खरीदार आए हैं। इसको देखते हुए इस संपत्ति की आवंटन दरें यथावत रखी गई हैं।

औद्योगिक भूखंड की दर में इजाफा

औद्योगिक भूखंड आवंटन के लिए शहर को तीन फेज में बांटा गया है। फेज-1 में सेक्टर 1 से 11, 16 और 16 ए आते हैं। दूसरे फेज में सेक्टर- 80, 140, 150 और 160 के दशक के औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, जबकि तीसरे फेज में कई सेक्टर है।

यहां मौजूदा दरें अधिकतम 44,800 रुपये और न्यूनतम 16,020 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर अधिकतम 47,490 रुपये और न्यूनतम 16,990 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गई हैं।

क्या हरियाणा में आईएनएलडी व बसपा के बीच हुए गठबंधन से तीसरे मोर्चे को एक-बार पुनः पंख लगेंगे?

कमलेश पांडे

जहां आम चुनाव 2024 में उनका संयुक्त वोट शेयर महज 3.15 प्रतिशत था, वहीं यदि 2019 के विधानसभा चुनाव के रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो बसपा को मात्र 4.21 फीसदी और इनेलो को 2.44 फीसदी वोट मिले थे।

लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने और सरकार चलाने के लिए क्षेत्रीय मित्र दलों पर निर्भर रहने से इलाकाई पार्टियों के हौसले बुलंद हैं।इनका कहना है कि एक दशक बाद ही सही, पर गठबंधन राजनीति का दौर एक बार फिर से लौट आया है। अलबत्ता, भाजपा के कमजोर होने और कांग्रेस की मजबूती के बाद इन दोनों दलों के खिलाफ काम करते रहने वाले तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। क्योंकि चुनावों में जब भी त्रिकोणात्मक संघर्ष की नौबत आती है तो प्रायः सत्तापक्ष लाभान्वित होता है। इस वर्ष के अंत में तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी इसका असर दिखाई पड़ेगा, जिसकी शुरुआत हरियाणा से हो चुकी है।

देखा गया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर वहां पर कभी सत्तारूढ़ रही इंडियन लोकदल और कभी यूपी में सत्ता में रही बहुजन समाज पार्टी ने एक-दूसरे से हाथ मिला लिया है। साथ ही, दोनों दलों के गठबंधन ने तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी है, जो एनडीए के साथ रही जननायक जनता पार्टी और इंडिया ब्लॉक के साथ रही आप आदि दलों को इस तीसरे गठबंधन के साथ लाने की कोशिश करेगी।

इस गठबंधन ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वह भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर चलेगी और अन्य सभी दलों को साथ लेकर चलेगी। समझौते के मुताबिक, 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के चुनाव में इनैलो 53 और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं, जब जजपा और आप इनके साथ होंगे तो इनैलो और बसपा अपनी सीटों में से उन्हें भी सम्मानजनक सीटें देंगी, ताकि तीसरा मोर्चा मजबूत हो।

इसलिए सियासी हल्के में यह चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि भारत के उपप्रधानमंत्री रहे और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवीलाल द्वारा स्थापित इंडियन लोकदल ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र और पार्टी के इकलौते विधायक अभय चौटाला के नेतृत्व में दलितों की पार्टी बसपा से जो हाथ मिलाने की पहल की है, उसका दूरगामी असर हरियाणा विधानसभा चुनाव समेत अन्य चुनावों पर पड़ेगा। क्योंकि बसपा के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे आकाश आनन्द ने यह घोषणा की है कि उनका गठबंधन अब बहुत दूर तक चलेगा।

चर्चा है कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से यह पता चल गया कि स्थानीय जाट और एससी वर्ग ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस को वोट दिया है, जिससे वह राज्य में मजबूती से पैर जमा चुकी है, तो उसे कमजोर करने के लिए राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर जाट परिवार के नेतृत्व वाली आईएनएलडी और दलित नेता मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी 10 साल बाद राज्य में सियासी लड़ाई के लिए एक साथ आई हैं।

जिस तरह से अचानक इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए अपने गठबंधन की औपचारिक घोषणा करने के लिए फिर से एक साथ आए हैं, उसके सियासी मायने साफ हैं। वह यह कि कांग्रेस को यहां मजबूत होने से रोका जाये, अन्यथा उनकी राजनीति पुनः खतरे में पड़ जाएगी। बताते चलें कि अप्रैल 2018 में आईएनएलडी ने 2019 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले मायावती के नेतृत्व वाली बसपा पार्टी के साथ गठबंधन किया था और सकारात्मक परिणाम भी

हासिल किया था। लेकिन 2018 में आईएनएलडी में विभाजन के बाद और 2019 के जींद उपचुनावों में आईएनएलडी के खराब प्रदर्शन के बाद ही बीएसपी ने गठबंधन खत्म करने का फैसला किया था। जो दोनों दलों के लिए आत्मघाती साबित हुआ। क्योंकि इससे पहले जब दोनों पार्टियों ने 1998 के लोकसभा चुनावों में गठबंधन किया था, तो हरियाणा में इनेलो ने 7 और बीएसपी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों ने क्रमशः 4 और 1 सीट जीती भी थी। जबकि वर्तमान में आलम यह है कि 90-सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में इनेलो के एकमात्र विधायक अभय चौटाला हैं, जबकि बीएसपी का कोई सदस्य नहीं है।

यही वजह है कि गत गुरुवार को हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनेलो महासचिव अभय चौटाला और मायावती के भतीजे व बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने घोषणा की कि हरियाणा स्थित पार्टी इनैलो 90 विधानसभा सीटों में से 53 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शेष 37 सीटें बीएसपी को दी गई हैं। वहीं, इस गठबंधन के हिस्से के रूप में नेताओं ने इनेलो नेता अभय चौटाला को अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने का फैसला किया है, जो एक मजबूत सियासी कदम है।

इस दौरान सीएम इन वेटिंग अभय चौटाला ने कहा कि हमने हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है। क्योंकि आज आम लोगों ने भी भाजपा को सत्ता से बाहर करने और कांग्रेस को दूर रखने का मन बना लिया है, जिसने दस साल तक राज्य को लूटा है। वहीं, बसपा नेता आकाश आनंद ने घोषणा की कि उनका गठबंधन केवल विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वे भविष्य में भी राज्य में अन्य चुनाव मिलकर लड़ेंगे। इससे साफ है कि बसपा जाट लैंड समझे जाने वाले पश्चिमी उत्तरप्रदेश से लेकर राजस्थान तक इस गठबंधन को भुनायेगी और खुद को और अधिक मजबूत बनाएगी।

उल्लेखनीय है कि इस गठबंधन की घोषणा के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ₹एक्स₹ पर पोस्ट किया कि बसपा और इनेलो मिलकर जनविरोधी पार्टियों को हराने और नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। इससे यह साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा का परोक्ष समर्थन करके बसपा को शून्य पर आउट करवाने वाली मायावती लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से सक्रिय हो चुकी हैं और यह उनका सबसे तगड़ा धमाका है। इससे अन्य राज्यों में भी बसपा को गठबंधन साथी मिलने के मार्ग प्रशस्त हो चुके हैं।

बकौल मायावती, ₹बहुजन समाज पार्टी व इण्डियन नेशनल लोकदल मिलकर हरियाणा में होने वाले विधानसभा आमचुनाव में वहाँ की जनविरोधी पार्टियों को हराकर अपने नये गठबन्धन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ लड़ेंगे, जिसकी घोषणा मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ आज चण्डीगढ़ में संयुक्त प्रेसवार्ता में की गयी।₹ वहीं, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां तक उम्मीद जताई कि दोनों दलों के बीच एकता से विरोधियों को हराने और नई सरकार बनाने में बहुत मदद मिलेगी।

उनकी इस घोषणा के बाद दिल्ली से हरियाणा तक यही चर्चा है कि भाजपा की बी टीम की तरह काम करने वाली मायावती अब क्या हरियाणा में कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगी? क्योंकि बीते आम चुनावों में हरियाणा में भाजपा की सीटें 10 से घटकर 5 रह गई, जबकि कांग्रेस ने 5 सीट झटक ली। कहने का तातपर्य यह कि वहां कांग्रेस ने बराबर-बराबर सीटें बांटीं। वहीं, खास बात यह कि सूबे में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित दो संसदीय सीटें अंबाला और सिरसा भी कांग्रेस के खाते में गई है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 विधानसभा क्षेत्रों में से 13 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं।

इस प्रकार आम चुनाव 2024 के नतीजों से साफ पता चलता है कि जाटों और अनुसूचित जातियों ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस को वोट दिया है। हालांकि अब जिस तरह से जाट परिवार की अगुआई वाली पार्टी इनेलो और दलित नेत्री मायावती की अगुआई वाली बसपा फिर से एक साथ आ गई है, तो सियासी हलकों में इस बात पर चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या इनैलो-बसपा गठबंधन हरियाणा में कांग्रेस का खेल बिगाड़ पाएगा, जो कि इस चुनाव को 10 साल बाद सत्ता में वापसी के एक सुनहरे अवसर के रूप में देख रही है।

इस बारे में स्थानीय राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि उन्हें इस गठबंधन से बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहां के जाट परिवार शुरू से ही दो खेमों में बंटे रहते हैं, जिसका मजबूत धड़ा हमेशा कांग्रेस के साथ रहता है। अभी कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां के कांग्रेस चेहरा हैं, इसलिए कांग्रेस की स्थिति जाटों के बीच मजबूत बनी रहेगी। वहीं, संविधान बचाने के लिए दलित और लोकतंत्र बचाने के लिए मुस्लिम अल्पसंख्यक भी उसके साथ बने रहेंगे। हालांकि, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इनैलो-बसपा यानी दोनों पार्टियों के पिछले चुनावी प्रदर्शन को देखना होगा।

जहां आम चुनाव 2024 में उनका संयुक्त वोट शेयर महज 3.15 प्रतिशत था, वहीं यदि 2019 के विधानसभा चुनाव के रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो बसपा को मात्र 4.21 फीसदी और इनेलो को 2.44 फीसदी वोट मिले थे। इसी प्रकार 2014 के आम चुनाव में बसपा का वोट शेयर महज 4.4 फीसदी था, जबकि इनेलो को 24.1 फीसदी वोट मिले थे, लेकिन वह अविभाजित इनेलो था। बहरहाल, 2018 में इनैलो के विभाजन के बाद से ही पार्टी काफी कमज़ोर हो गई है। यही वजह है कि गत लोकसभा चुनाव में जाट और दलित कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े थे और जब तक राज्य सियासत में कुछ नाटकीय परिवर्तन नहीं होता है, तब तक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन खोना असंभव है। वहीं, अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस के प्रदर्शन से पता चलता है कि दलितों ने भी इस बार पार्टी का समर्थन किया है।

इसके अलावा, आम चुनाव 2024 में इनेलो और बसपा ने क्रमशः 7 और 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और दोनों ही दलों की सीटें खाली रहीं, क्योंकि इनका खाता भी यहां नहीं खुला। जहां तक वोट शेयर की बात है तो इनेलो का वोट शेयर मात्र 1.87 फीसदी रहा, जबकि बसपा को 1.28 फीसदी वोट मिले। इससे साफ है कि नया गठबंधन राज्य में सरकार बनाने में सफल होगा या नहीं, यह तो बाद की बात है, लेकिन कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं पर तुषारापात कर सकता है। मायावती का प्राथमिक लक्ष्य भी यही है, क्योंकि भाजपा की मजबूती में ही उनका परोक्ष हित निहित है।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर

टाटा टियागो ईवी और एमजी कॉमेट ईवी को टक्कर देगी यह ईवी कार

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। मुंबई स्थित स्टार्टअप पीएमवी (पर्सनल मोबिलिटी व्हीकल) ने देश की सबसे छोटी और सस्ती इलेक्ट्रिक कार पेश की है।

PMV EaS-E कंपनी की ही नहीं बल्कि देश की भी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार साबित हो रही है। इस कार की बुकिंग भी बेहद आसान है। कंपनी के मुताबिक आप इस कार को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से सिर्फ 2 हजार रुपये की टोकन राशि देकर बुक कर सकते हैं। इस कार की लंबाई महज 2915 mm है। इसके अलावा कंपनी के मुताबिक एक बार फुल चार्ज होने पर यह कार करीब 160 किलोमीटर की रेंज प्रदान करती है।

कंपनी की इस इलेक्ट्रिक कार को 15 एम्पियर सॉकेट से चार्ज किया जा सकता है। इस कार को फुल चार्ज होने में करीब 4 घंटे का समय लगता है। कंपनी ने इस कार को 2022 में पेश किया था। हालांकि इसे अभी लॉन्च नहीं किया गया है। इस कार का मुकाबला टाटा टियागो ईवी और एमजी कॉमेट ईवी से है। साथ ही पीएमवी की कार इन गाड़ियों से काफी सस्ती भी है।

अगर फीचर्स पर गौर करें तो इस कार का आकार छोटा होने की वजह से इसे आसानी से कहीं भी पार्क किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें ड्राइवर सेंसिटिव ऑटोमैटिक अनलॉक, रिमोट पार्किंग असिस्ट, रिमोट कंट्रोल एसी, ओटीए, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट और रियर एलईडी लाइट्स, एलॉय व्हील्स, स्विच कंट्रोल स्टीयरिंग के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

अभी तक कंपनी ने इसकी वास्तविक कीमत का खुलासा नहीं किया है। लेकिन इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा और माना जा रहा है कि कंपनी इसे 4 से 5 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत के अंदर लॉन्च कर सकती है। साथ ही इसका लुक भी बेहद प्यारा है जो इसे अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों से अलग बनाता है।

अमरावती में 300 महिलाएं चलाएंगी गुलाबी ई-रिक्शा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। राज्य सरकार के हाल ही में पेश किए गए बजट में राज्य के 17 जिलों में 10 हजार महिलाओं को ई-पिंक रिक्शा दिए जाएंगे। इस में अमरावती भी शामिल है। 10 हजार ई-पिंक रिक्शा में से 300 लाभार्थियों का चयन अमरावती जिले से भी किया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

ई-पिंक रिक्शा के लिए 10 प्रतिशत राशि लाभार्थी महिलाओं या लड़कियों को वहन करनी होगी। ई-पिंक रिक्शा का 70 प्रतिशत ऋण शहरी सहकारी बैंकों, जिला बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों से उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार वित्तीय भार का 20 प्रतिशत वहन करेगी जबकि लाभार्थी पिछले पांच वर्षों में ऋण चुकाने के लिए जिम्मेदार है। अमरावती सहित चयनित 17 शहरों में जहां महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित यात्रा कर सकें, नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, इच्छुक महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने और ड्राइविंग के लिए अन्य सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इच्छुक महिलाओं को ई-पिंक रिक्शा के लिए जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी से आवेदन करना होगा।

योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन, लाभार्थी का आधार कार्ड और पैन कार्ड, महाराष्ट्र राज्य का निवास प्रमाण पत्र, परिवार के मुखिया का आय प्रमाण पत्र, वार्षिक आय तीन लाख से कम, बैंक खाता पासबुक, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्रा इविंग लाइसेंस लाभार्थी रिक्शा केवल चलाएगा आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

योजना के तहत हितग्राहियों के चयन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। सदस्य में परिवहन अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा एवं श्रम विभाग के अधिकारी, महिला आर्थिक विकास निगम के जिला समन्वयक, शहरी बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं संबंधित जिले के महिला बाल विकास अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।

ई-पिक रिक्शा का संचालन महिला लाभार्थी द्वारा किया जा रहा है, इसकी जांच करने की जिम्मेदारी यातायात नियंत्रक पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग की होगी। ई-पिंक रिक्शा को पुरुष चलाते हुए पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

"परिवहन विशेष" ने ईवी ड्राइव द फ्यूचर के दीपक स्मिता श्रीवास्तव को ईवी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु मीडिया अवॉर्ड से नवाजा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। देश की राजधानी स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में शनिवार 06 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम में जनकल्याण, सड़क सुरक्षा, जाम व दुर्घटना मुक्त सड़कें, महिला सुरक्षा व अन्य विशिष्ट कार्यों के साथ-साथ शिक्षा, चिकित्सा, समाज सेवा, साहित्य, पत्रकारिता, पर्यावरण आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले देशभर से आये 70 से अधिक लोगों को पुरस्कार व पौधे देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री सतीश चंद्रा जी (सेवानिवृत्त) के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हुईं और उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया। दीपक स्मिता श्रीवास्तव को भारत सरकार के संयुक्त आयुक्त अमर पाल सिंह जी के कर कमलों द्वारा परिवहन विशेष की तरफ से अवार्ड और पौधा देकर प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें ईवी क्षेत्र में सकारात्मक पत्रकारिता के लिए दिया गया हैं।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परिवहन विशेष ने इतनी बड़ी संख्या में पर्दे के पीछे समाज में काम करने वालों को एक साथ जोड़ने में जो कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी के लिए परिवहन विशेष के मुख्य संपादक संजय बाटला जी एवं उनकी टीम बन्धुओं को नमन और अभिनंदन करते हैं।

ईवी को बढ़ावा देने के लिए सियाम ने मांगी रियायतें ताकि कबाड़ से होने वाले वाहनों को मिले अतिरिक्त प्रोत्साहन

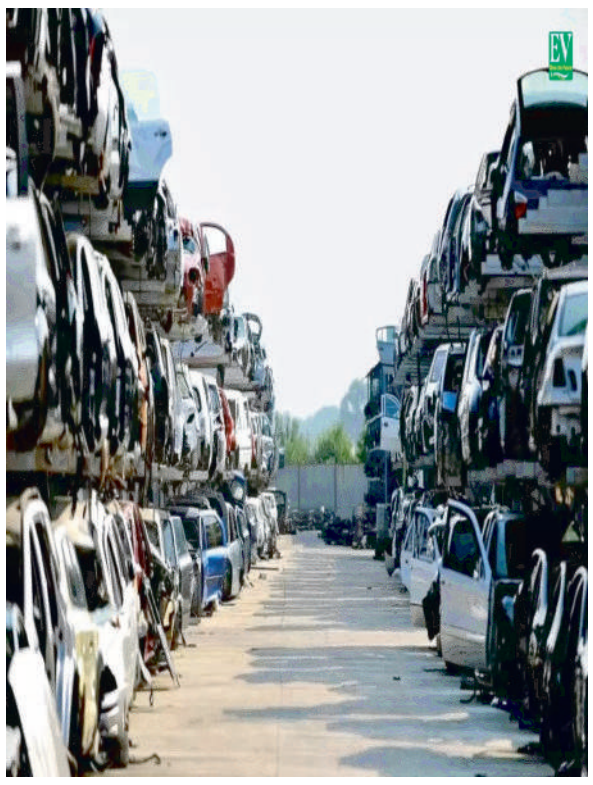

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। वाहन उद्योग संगठन सियाम ने शुक्रवार 12 जुलाई को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए रियायतों की मांग की। उद्योग निकाय ने यह भी कहा कि सरकार को आगामी केंद्रीय बजट में वाहनों को स्क्रैप करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की घोषणा करनी चाहिए। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने पूंजीगत व्यय के लिए अधिक आवंटन के साथ विकास को बढ़ावा देने वाले बजट की मांग की है।

सियाम के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार फेम 3 जैसी नीति लाएगी। पीएलआई जैसी अच्छी योजनाएं पहले से ही लागू हैं, जिनके जारी रहने का हमें भरोसा है। अगर फेम 3 योजना शुरू की जाती है, तो इससे इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के साथ-साथ सार्वजनिक बसों को वित्तीय प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। फेम 3 योजना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम यानी ईएमपीएस की जगह लेगी, जिसे फेम 2 योजना के खत्म होने के बाद शुरू किया गया था।

विनोद अग्रवाल ने कहा कि हम यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन पर कुछ और घोषणाएं करें। उन्होंने कहा कि पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को स्क्रैप करने को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार को ऐसी पहल जारी रखनी चाहिए जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी हों। हमें उम्मीद है कि एक बार फिर यह विकासोन्मुखी बजट होगा, जिसका मतलब है कि पूंजीगत व्यय पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

ईजेड-ऑटोशाला प्राइवेट लिमिटेड और टेरा चार्ज ने ईवी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए की रणनीतिक साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अग्रणी सेवा प्रदाता ईजेड-ऑटोशाला प्राइवेट लिमिटेड और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग समाधानों में अग्रणी टेरा चार्ज ने ईवी चार्जिंग स्टेशनों की पहुंच और सुविधा में तेजी लाने के उद्देश्य से एक रणनीतिक साझेदारी की है।

ईजेड-ऑटोशाला के निदेशक संजय रस्तोगी ने कहा कि टेरा चार्ज के साथ हमारा सहयोग एक अधिक मजबूत ईवी चार्जिंग समाधानों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आगे कहा कि हम तिपहिया इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ईवी बुनियादी ढांचे के लिए टेरा चार्ज के तकनीकी विशेषज्ञता के साथ चार्जिंग समाधानों के लिए एक नया मानक स्थापित कर रहे हैं।

ईजेड-ऑटोशाला के निदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि टेरा चार्ज के इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य न केवल बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है बल्कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जहां टिकाऊ इलेक्ट्रिक तिपहिया परिवहन को न केवल प्राथमिकता दी जाएगी बल्कि शहरी गतिशीलता के लिए सबसे सुविधाजनक और किफायती विकल्प भी बनाएं जाएंगे।

टेरा चार्ज के सीईओ अकिहिरो उएदा ने भारत में टिकाऊ गतिशीलता को आगे बढ़ाने में सहयोग और ईजेड-ऑटोशाला के साथ निरंतर सहयोग के माध्यम से ई-मोबिलिटी चुनौतियों पर काबू पाने में विश्वास व्यक्त करते हुए सुलभ ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण के साझा लक्ष्य पर जोर दिया।

ऑटो-लेक इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक और पावरट्रेन घटकों का एक प्रमुख निर्माता

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधान प्रदान करने वाली कंपनी ऑटो-लेक इलेक्ट्रिक ने पुणे में इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के उत्पादन के लिए अपनी पहली पावरट्रेन फैक्ट्री का निर्माण किया है।

इस पावरट्रेन फैक्ट्री में अत्याधुनिक उत्पादन और असेंबली लाइनें हैं, जिनमें उत्पादकता, पर्यावरणीय स्थिरता और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए नवीनतम तकनीकों को शामिल किया गया है।

भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" पहलों के अनुरूप, यह सुविधा स्थानीय विनिर्माण और अभिनव और पर्यावरण के प्रति जागरूक मोबिलिटी उत्पादों और समाधानों की इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

इस नई विनिर्माण सुविधा के साथ, ऑटो-लेक इलेक्ट्रिक अपने ग्राहकों की सभी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जरूरतों के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदाता बनकर बाजार में अग्रणी बनने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

पानी में चलेगी, खतरों से खेलेगी टाटा की नई ईवी एसयूवी कार

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स अपनी नई इलेक्ट्रिक कार को पूरे जोर-शोर से लाने के लिए तैयार है। टाटा कर्व ईवी का नया टीजर सामने आया है। टाटा जल्द ही इस इलेक्ट्रिक कार को भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है। कर्व ईवी के नए टीजर में इस कार का टेस्टिंग मॉडल देखा जा सकता है। इस नए टीजर में यह कार पानी में चलती हुई भी नजर आ रही है।

टाटा मोटर्स एक के बाद एक इस इलेक्ट्रिक कार के टीजर लॉन्च कर रही है। इन टीजर के जरिए कार की परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी दी जा रही है। नए टीजर में कार पानी से गुजरती नजर आ रही है। यह कार 26.6 डिग्री की खड़ी ढलान वाले पुल पर आसानी से चढ़ती और उतरती है। इसके साथ ही टीजर में कार को पुल से उतरते समय रिवर्स करते हुए भी दिखाया गया है।

टाटा कर्व के पिछले टीजर में इस एसयूवी में लगाए गए पैडल शिफ्टर्स के बारे में बताया गया था, जिसके जरिए इसके गियर बॉक्स को मैनुअली कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही यह भी जानकारी दी गई थी कि कार में ड्राइवर के लिए डिजिटल डिस्प्ले भी लगाया गया है। इसके अलावा इस कार के तीन ड्राइविंग मोड्स के बारे में भी जानकारी दी गई थी। टाटा कर्व तीन राइडिंग मोड्स इको, स्पोर्ट और सिटी के साथ बाजार में आने वाली है।

टाटा कर्व तीन पावरट्रेन ऑप्शन के साथ बाजार में आने वाली है। इस कार में तीन पावरट्रेन ऑप्शन होंगे- पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक। टाटा सबसे पहले कर्व का इलेक्ट्रिक वेरिएंट बाजार में उतार सकती है। इसके बाद ही कर्व के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट लॉन्च किए जाएंगे।

टाटा की यह नई इलेक्ट्रिक कार active.ev प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकती है। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पहले पंच ईवी में भी किया जा चुका है। यह इलेक्ट्रिक कार सिंगल चार्जिंग में करीब 500 किलोमीटर की रेंज के साथ आ सकती है। इस कार को चार्ज करने के लिए डीसी चार्जिंग का ऑप्शन दिया जा सकता है।

मुस्लिमों को कूपमंडूक बनाए रखना चाहते हैं दल

योगेंद्र योगी

बिल को पास कराने के लिए एनडीए को 121 सदस्यों का समर्थन चाहिए था, लेकिन सांसदों की बड़ी संख्या में अनुपस्थिति की वजह से सदन में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो गई और वह बिल पास कराने में सफल रही। विपक्ष के भागने की वजह यह रही कि भाजपा इसे मुद्द बना कर मुस्लिम महिलाओं से उनके खिलाफ धरना-प्रदर्शन नहीं करवा दे।

यदि ये दोनों अधिकार कांग्रेस आजादी के बाद मुस्लिम महिलाओं को कानूनी तौर पर मुहैया करा देती तो आज देश में मुसलमानों के विकास की सूरत अलग होती। किसी भी शिक्षित और जागरूक कौम को आसानी से बरगलाया नहीं जा सकता। गैर भाजपा विपक्षी दलों ने मुसलमानों को जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए भी पर्याप्त कदम नहीं उठाए। मुसलमानों के विकास के सपने धराशायी हुए हैं'

गैर भाजपा राजनीतिक दलों में विशेषकर कांग्रेस ने मुस्लिमों के वोट पाने के लिए उनके अधिकारों को लेकर कभी भी पहल नहीं की। यही वजह रही कि देश का मुस्लिम वर्ग विकास की मुख्य धारा में शामिल होने से पिछड़ गया। इतना ही नहीं, गैर भाजपा दलों ने जब कभी मुसलमानों की भलाई का मौका आया तब नजरें चुरा ली, बल्कि सत्ता में आने पर पुरानी स्थिति बहाल करने तक का वादा किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। मुस्लिम महिला को पति से गुजारा भत्ता देने की मांग की याचिका थी। कोर्ट ने कहा सभी महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 की मदद ले सकती हैं। यह कानून सभी धर्म की महिलाओं पर लागू होता है। गुजारे भत्ते के लिए अपने पति के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन गॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाया। इस फैसले को गैर भाजपा दल गले नहीं उतार पा रहे हैं। इसी तरह तीन तलाक के फैसले को लेकर कांग्रेस सहित दूसरों दलों ने विरोध किया था। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए तीन तलाक के फैसले को पलट कर वापस तीन तलाक लागू करने का वादा किया था। इससे पहले शाह बानो पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने कानून में संशोधन करके बदल दिया था। कांग्रेस ने यह सब किया वोट बैंक की खातिर, किन्तु वह भी बच नहीं सका। दूसरे दल मुसलमानों की भलाई की आड़ में अपना उल्लू सीधा करने में ज्यादा आगे निकल गए। गैर कांग्रेस दलों में प्रमुख रूप से पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटों की खातिर आतंकवाद के आरोपियों से समझौता तक करने में गुरेज नहीं किया। शाह बानो केस में राजीव गांधी की सरकार ने वोट बैंक की खातिर कोर्ट का फैसला बदल दिया था।

शाह बानो ने 1978 में इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने

अदालत से गुजारिश की कि उनके पति को उन्हें गुजारा भत्ता देने के लिए निर्देश दिया जाए। साल 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल को अपनी तलाकशुदा बीवी को 20000 रुपए गुजारा भत्ता देने को कहा था। समद ने अपनी बीवी को तीन तलाक दिया था। इसके जवाब में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 लागू कर दिया। इस अधिनियम ने तलाक के बाद केवल 90 दिनों तक मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया। इसी तरह मुस्लिमों की आधी आबादी के पक्ष में जब तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किया गया तब भी गैर भाजपा दलों ने काफी हायतौबा मचाई थी। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने 22 अगस्त 2017 को अपने फैसले में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने 1400 साल पुरानी प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था और सरकार से कानून बनाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने कानून बनाते हुए एकसाथ तीन बार तलाक बोलकर या लिखकर निकाह खत्म करने को अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया। इस अपराध के लिए अधिकतम तीन साल कैद की सजा का प्रावधान भी है। तीन तलाक के मुद्दे पर गैर भाजपा दलों का असली चेहरा तब सामने आया जब संसद में इसके मामले में कानून पास करने से पहले वोटिंग हुई। गैर भाजपा दल ट्रिपल तलाक के खिलाफ थे, लेकिन राज्यसभा से वोटिंग के पहले भाग गए। इनमें बसपा के 4, सपा के सात, एनसीपी के 2, पीडीपी के 2, कांग्रेस के 5, टीएमसी, वामपंथी पार्टियों, आरजेडी, डीएमके और वाईएसआर कांग्रेस के एक-एक सांसद अनुपस्थित रहे।

बिल को पास कराने के लिए एनडीए को 121 सदस्यों का समर्थन चाहिए था, लेकिन सांसदों की बड़ी संख्या में अनुपस्थिति की वजह से सदन में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो गई और वह बिल पास कराने में सफल रही। विपक्ष के भागने की वजह यह रही कि भाजपा इसे मुद्द बना कर मुस्लिम महिलाओं से उनके खिलाफ धरना-प्रदर्शन नहीं करवा दे। बिल पर बहस के दौरान वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई ने कहा कि बिल का मैं 6 कारणों से विरोध करता हूं। लेकिन वोटिंग के दौरान विजय साई सदन में अनुपस्थित थे। बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा का कहना था कि हमारी पार्टी इस बिल के खिलाफ है और इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकार दिया है और आप फिर से इसे अस्तित्व में लाना चाहते हैं। इस बिल से महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित होने वाली हैं, क्योंकि पुरुष के जेल जाने के बाद महिलाएं भी कहीं की नहीं रह जाएंगी। सरकार न बच्चों की देखरेख करेगी और न महिलाओं को गुजारा भत्ता देगी, ऐसे में उनका जीवन कैसे चलेगा। तीन तलाक पर इस तरह मुखर होने के बावजूद बसपा का कोई सांसद सदन में उपस्थित नहीं था। एनसीपी सांसद माजिद मेमन ने भी बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप किसी को बगैर अपराध के 3 साल की सजा देने जा रहे हैं, तलाक कहना कोई अपराध नहीं है। जेल में जाने के बाद भी शादी खत्म नहीं होगी और महिला को गुजारा भत्ता के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। जेल में रह रहा पति कैसे पत्नी को भत्ता दे पाएगा, ऐसे में कानून फेल हो गया। यह बिल पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। मगर जब बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए सदन में वोटिंग हो रही थी, उस दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल उपस्थित नहीं थे। तीन तलाक बिल का विरोध करने वाले एनडीए के सहयोगी दल तो वॉकआउट कर गए जिनमें अन्नाद्रमुक, जेडीयू शामिल हैं। गैर-एनडीए और गैर-यूपीए टीआरएस सदन में गैर मौजूद रही।

कांग्रेस के अल्पसंख्यक महाधिवेशन में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आई, तो नरेंद्र मोदी सरकार के लाए ट्रिपल तलाक कानून को खत्म कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ये कानून मुस्लिम पुरुषों को जेल में भेजने की एक साजिश है। इस सम्मेलन में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। लेकिन कोई भी कांग्रेस नेता एक लफ्ज तक नहीं बोला। तीन तलाक पर पाबंदी का फैसला हो या मेंटीनेंस पाने का हक, मुस्लिम आधी आबादी लंबे अर्से से अपने अधिकारों के प्रति अंधेरे में रही है। उलेमाओं और मौलवियों ने ऐसे अधिकारों का हमेशा से विरोध किया है। वोट बैंक के लालच में कांग्रेस सहित दूसरे दलों ने हमेशा मुस्लिम महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने की पैरवी की है। यदि ये दोनों अधिकार कांग्रेस आजादी के बाद मुस्लिम महिलाओं को कानूनी तौर पर मुहैया करा देती तो आज देश में मुसलमानो के विकास की सूरत अलग होती। किसी भी शिक्षित और जागरूक कौम को आसानी से बरगलाया नहीं जा सकता। गैर भाजपा विपक्षी दलों ने मुसलमानों को जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए भी पर्याप्त कदम नहीं उठाए। यहां तक कि मुसलमानों के खैरख्वाह बनने का दंभ भरने वाले राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तक नहीं दिया। यही वजह रही कि आजादी के बाद जितनी तरक्की मुसलमानों को करनी चाहिए थी, उसकी तुलना में पिछड़ गए। मुसलमानों के विकास के सपने धराशायी हुए हैं।

संपादक की कलम से

संविधान या शरिया

अब वक्त आ गया है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर इसका आग्रह किया है। संविधान में इसका प्रावधान है। संसद और भारत सरकार यह भी स्पष्ट करें कि देश संविधान से चलेगा अथवा शरिया कानून भी संवैधानिक माना जाता रहेगा? मुसलमानों के पर्सनल लॉ पर प्रहार करने की हमारी नीयत और मानसिकता नहीं है। पर्सनल लॉ तो सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध आदि समुदायों के भी हैं। आदिवासी कबीलों से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि मुस्लिम देश की दूसरी बहुसंख्यक आबादी हैं। स्पष्ट किया जाए कि जो मुद्दे सामुदायिक और राष्ट्रीय किस्म के हैं, धर्म, मजहब, जाति से ऊपर हैं, कमोबेश उनके संदर्भ में अब 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (बीएनएसएस) की धाराएं लागू होनी चाहिए। वे हिंदू-मुस्लिम समेत सभी समुदायों पर, समान रूप से, प्रभावी होनी चाहिए। यही समान नागरिक संहिता का निष्कर्ष है। शरिया और कुरान की आड़ में छिपने वाला मुसलमान सबसे पहले 'भारतीय' है और यही उसकी पहचान है। यदि देश भर में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, तो संभव है कि मुस्लिम इतना भड़क जाएं कि हिंसा का माहौल बन जाए! घरेलू हिंसा से उपजे हालात सांप्रदायिक दंगों में तबदील हो जाएं! तेलंगाना में सरेआम संवैधानिक प्रावधानों और बाल विवाह कानून समेत कई कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किशोर बच्चियों का दैहिक शोषण किया जा रहा है। संसद 2019 में तीन तलाक के खिलाफ विधेयक पारित कर कानून बना चुकी है। फिर भी मुस्लिम मर्द 15-16वीं सदी के समाज में जीना चाहता है! भारत एक संवैधानिक गणतंत्र है अथवा केला गणतंत्र'! क्या ऐसा संवैधानिक उल्लंघन जारी रहेगा? मुद्दा सर्वोच्च अदालत के हालिया फैसले से फिर उभरा है। दो न्यायाधीशों की पीठ का आदेश है कि मुस्लिम मर्द (पति) तलाकशुदा पत्नी को न्यायिक गुजारा-भत्ता देगा। अदालत के इस फैसले के तुरंत बाद मुस्लिम धर्मगुरु, मौलाना, नेता, विशेषज्ञ आदि चीखने लगे, बौखला उठे और तिलमिलाने लगे कि यह फैसला शरिया के खिलाफ है।

शरिया और कुरान में मुस्लिम तलाकशुदा औरत को गुजारा-भत्ता का कोई जिक्र नहीं है। मामले को 1986 के 'शाहबानो प्रकरण' की ओर मोड़ा जाने लगा है। उस समय संसद ने सर्वोच्च अदालत का फैसला पलट दिया था और तत्कालीन सरकार ने मुस्लिम मौलानाओं के दबाव में, वोट की खातिर, घुटने टेकते हुए ऐसा कानून बनाया, जो आत्मा से मुस्लिम औरत के खिलाफ था। शाहबानो भी 40 साल के वैवाहिक जीवन और 5 बच्चों को जन्म देने के बाद सड़क पर आई थी, लिहाजा उसे अदालत की शरण में जाना पड़ा। क्या मुसलमानों में विवाह की परिणति यही होती है कि जब मन आया, तब औरत को छोड़ दिया और गुजारा-भत्ता भी नहीं दिया। कहा जाता है कि अब 'इद्दत' के तीन महीनों के दौरान ही तलाकशुदा औरत को गुजारा-भत्ता दिया जाता है और बच्चों की परवरिश के लिए मात्र दो साल की उम्र तक आर्थिक मदद दी जाती है। उसके बाद की जिंदगी की जिम्मेदारी मुस्लिम औरत पर ही है। सवाल है कि क्या कुरान और शरिया में ऐसी मानवीय क्रूरता के जिक्र हैं? क्या तीन माह के बाद औरत का और 2 साल की उम्र के बाद बच्चे का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है? आखिर वे औलादें कहां से और कैसे आई हैं? ये तमाम विवादास्पद सवाल हो सकते हैं। सोच और उसकी व्याख्याएं भी भिन्न हो सकती हैं। शरिया और कुरान को सांगोपांग शायद ही किसी ने पढ़ा हो, लेकिन क्या सर्वोच्च अदालत के फैसले और बीएनएसएस की धारा 144 की अवमानना की जा सकती है? क्या ऐसा करना अपराध नहीं होगा? संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों और आरक्षण के लिए तो मुस्लिम मौलानाओं को खूब याद आता है, लेकिन औरत के भरण-पोषण सरीखा मुद्दा हो, तो शरिया की आड़ लेने लगते हैं। दरअसल यह मामला सामाजिक समानता और लैंगिक समानता का ज्यादा है। संविधान ने दोनों ही स्थितियों के लिए समता का अधिकार दिया है।

चर्चा

निजी क्षेत्र के घोड़े क्यों नहीं

प्रगति की सुर्खियों को सरकार से बटोरते-बटोरते आज हर इंतजाम के लिए कर्ज में अमानत गिरवी है। हम छवि के मुहाने पर तब कर्जदार नजर आते हैं जब वित्त आयोग हमारे ऑडिट में नजरें गड़ाकर सवाल पूछता है, लेकिन विकास के सफर में हम भूल जाते हैं कि यहां निजी क्षेत्र के घोड़े सिर्फ हरितिमा मांग रहे हैं। कर्ज हमारे फलक पर एक लाख करोड़ की सीमा को लांघने के लिए बेताब है, लेकिन प्रगति के मोहल्ले में शोर है कि यूं हाथ पे हाथ धरे कब तक बैठेंगे। हिमाचल की सूरत में एशिया विकास बैंक की परिपाटी में घूम रहीं परियोजनाओं में पर्यटन बलि का बकरा बनने लगा है। सत्ता की खिड़कियां जहां खुल गईं, वहां प्रगति के मुहावरे में एडीबी की कमर कस कर देखा जाता है। इसका यह अर्थ नहीं कि इस फंडिंग से पर्यटन का सरकारी ओहदा कमाऊ हो गया या आइंदा हो जाएगा। पर्यटन बनाएगा, सजाएगा और पर्यटन निगम के हवाले से वही ढाक के तीन पात। आधे से ज्यादा संपत्तियां सिर्फ गंवा रही हैं, पर्यटन निगम के चूल्हे की कमाई, फिर भी हम इजाफे की उम्मीद में आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि पर्यटन की अवधारणा में राज्य की क्षमता और महत्त्वाकांक्षा है, लेकिन अफसोस कि पूरे राज्य की तस्वीर में कभी मुकम्मल जहां नहीं देखा। अगर दिल किया या नूरपुर में सत्ता की शक्ति परवान चढ़ गई, तो पर्यटन के दो यूनिट बनकर बर्बाद हो जाते हैं। क्षमता दिखाने से पहले कई कैफे बिक जाते हैं या भागसूनाग का जलधारा कैफे मॉल बनकर किसी निजी निवेशक के पांव की धूल बन जाता है। अब फिर से एक मुहिम हाईवे पर पर्यटन परिसरों की जमात में आगे बढ़ना चाहती है, जहां सार्वजनिक जमीन पर एडीबी का धन और सत्ता का मन एक साथ काम करेगा। नादौन और औहर में पर्यटन महत्त्वाकांक्षा के सपने पूरे हो रहे हैं तो हाईवे पर्यटन के इच्छाधारी लक्ष्यों की बानगी में पर्यटन निगम का फलता-फूलता संसार देखा जाएगा। जहां चाह हो वहां राह मिलती, लिहाजा हर पांच साल बाद और सत्ता परिवर्तन के साथ यही चाह क्यों बदल जाती है। अगर सरकारी संपत्तियों के निरर्थक अस्तित्व का ऑडिट करें, तो कमोबेश हर विधानसभा क्षेत्र में कई सवाल मिल जाएंगे जहां इस्तेमाल के बिना, आवश्यक मरम्मत के बिना और आधे-अधूरे निर्माण में लुटी पिटी इमारतें मिल जाएंगी। बिलासपुर-शिमला के बीच निजी क्षेत्र के ढाबे-रेस्तरां मिल जाएंगे, लेकिन भराड़ीघाट के समीप पर्यटन निगम के रेस्तरां के ताले मिल जाएंगे। ऐसे में क्या पर्यटन निगम से कभी पूछा गया कि अगले दस से बीस साल में वह करना क्या चाहता है या उसके हक का वास्तविक विस्तार होगा क्या। अगर पर्यटन निगम के लक्ष्यों में नई इमारतों के सांप ही डालने हैं तो वर्षों पहले हमीरपुर में उखली के समीप खुले पर्यटक सूचना केंद्र से पूछ कर देखें कि वह किसी एक पर्यटक से भी संवाद करने से पहले क्यों मर गया। हैरानी है कि भाखड़ा और पौंग बांध के किनारों पर सरकारी व्यय की कई पर्यटन इकाइयां निरर्थक हो गईं, लेकिन अभियान जारी है। यह दीगर है कि कभी-कभी निजी निवेश के लिए बयानबाजी होती रहती है या इन्वेस्टर मीट तक हो जाती है, लेकिन पर्यटन की संभावनाओं में पहाड़ के दरख्त सदा पतझड़ में रहते हैं। ऐसे में अगर हिमाचल के होटल, पर्यटन उद्योग और परिवहन के निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए तो सारा प्रदेश पर्यटन राज्य बन जाएगा। उदाहरण हमारे सामने है। दस सालों के प्रयास ने बीड़-बिलिंग को करीब ढाई-तीन सौ निजी पर्यटन इकाइयों से भर दिया है। हम अगर चाहें तो आठ-दस प्रमुख टेंपल सिटी के विकास में निजी क्षेत्र के सहयोग से पर्यटन के नए नक्शे और आर्थिकी के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, वरना एडीबी के फंड से आधी-अधूरी और बर्बाद भवनों की कुर्बानी गिन लेनी चाहिए।

प्रताप सिंह पटियाल

कातिलाना शौक की आगोश में युवावेग

बहरहाल आगाज-ए-जवानी में गन कल्चर की उल्फत में डूब रहे युवाओं से अपील है कि यदि हथियारों से खेलने का शौक है, तो दुनिया की सर्वोत्तम भारतीय थल सेना का हिस्सा बनें। सेना में प्रशिक्षण के साथ कई किस्म के आधुनिक हथियारों से मुखातिब होने का मौका मिलेगा'

किसी भी राष्ट्र का बेहतर मुस्तकबिल उस मुल्क की युवाशक्ति से तय होता है। तवानाई से मुराद युवा ताकत मुल्क के किसी भी हिस्से में इंकलाब लाने की सलाहियत रखती है। सशस्त्र सेनाओं से लेकर देश के हर क्षेत्र में युवाओं की जरूरत रहती है। लेकिन यदि मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया युवावेग बुनियादी अखलाक तथा अच्छी तालीम व तरबियत से महरूम रहकर नाफरमान होकर जुर्म की दुनिया में मुकाम तलाशने पर आमादा हो जाए तो अभिभावकों के अरमान अश्क बनकर बह जाते हैं। चूंकि इनसान की परवरिश में पारंपरिक संस्कार बहुत मायने रखते हैं। यदि तालीम व तरबियत की बुनियाद मजबूत हो तो इनसान का जमीर खुद उसके किरदार को महफूज रखता है। आधुनिक दौर में कुछ जानलेवा शौक युवावर्ग को अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं, मसलन तीव्रता से बजकर दिल की धड़कन को तेज करने वाला म्यूजिक, नशे की तलब व गन कल्चर की ख्वाहिश तथा सड़कों पर मौत का मंजर पेश करने वाली वाहनों की तेज रफ्तार जैसे कातिलाना शौक युवाओं के अहबाब बन रहे हैं। देश रक्षा के महाज पर दास्तान-ए-सुजात के मजमून लिखने वाली भारतीय सेना युवाओं के लिए सबसे बड़ा प्रेरणास्रोत है। खेल मैदानों पर जोर आजमाईश करके हमारे खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय खेल पटल पर तिरंगा लहराकर हिंदोस्तान को गौरवान्वित कर रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर व वैज्ञानिक आलमी सतह पर भारत का मान-सम्मान बढ़ा रहे हैं। मगर विडंबना है कि ज्यादातर युवा सियासी रहनुमाओं व मायानगरी के अदाकारों को अपना आदर्श मानते हैं। सियासतदानों व सिल्वर स्क्रीन के अदाकारों के साथ फोटो खिंचवाना भी प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है।

यदि युवापीढ़ी में नशाखोरी, गैंगस्टर व गन कल्चर जैसे नदामत का सबब बन चुके शौक पनप रहे हैं, तो सियासत व बॉलीवुड के नुमाया किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश के कई सियासी रहनुमां तथा मायानगरी के कई अदाकार 'आम्र्स एक्ट' व 'गैंगस्टर एक्ट' के तहत सलाखों के पीछे जा चुके हैं। आधुनिक म्यूजिक में अश्लील लफ्फाजी तथा फिल्मों में नशीली बज्म व गन कल्चर की झलक साफ दिखती है। लोकप्रियता की बुलंदी पर पहुंचने के लिए कई फनकार अपने नगमों में मादक पदार्थों व हथियारों का महिमामंडन बखूबी करते हैं। गन कल्चर, नशीली बज्म, हुक्का बार व गैंगस्टर संस्कृति की प्रमोशन करने वाले सिनेमा व संगीत जगत ने युवाओं के जहन में काफी हद तक अपना प्रभाव छोड़ दिया है। शादी समारोह व कई अन्य कार्यक्रमों में फायरिंग करके अपनी हैसियत व रुतबे की नुमाइश की जाती है। देश के कई राज्य हथियारों की कालाबाजारी के लिए मशहूर हो चुके हैं। चुनावों के दौरान कई राज्यों में लाइसेंसी हथियार जमा करने में सुरक्षा एजेंसियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। स्मरण रहे कोई भी इनसान पैदाइशी गैंगस्टर या तस्कर नहीं होता और न ही कोई माफिया या बाहुबली फलक से टपकता है। गैंगस्टर, डॉन, मफिया, बाहुबली, अलगाववादी व चरमपंथी बनने की दास्तान के पीछे कहीं न कहीं जम्हूरी निजाम की हिमायत व सरपरस्ती जरूर हासिल होती है। आम लोगों व सुरक्षा एजेंसियों के लिए

गर्दिश पैदा करने वाले इन मसलों को रुखसत करने में वोट बैंक के चलते सियासत भी खामोश रहती है। जबकि सुशासन की कसौटी का मतलब कानून की हुक्मरानी होता है। देश में गैंगस्टर व हथियार संस्कृति के पनपने से कारोबारियों व कई अन्य लोगों से रंगदारी, अवैध वसूली व अपहरण की धमकी देकर फिरौती मांगना भी एक धंधा बन चुका है। जेलों में गैंगवार तथा गैंगस्टरों के भागने की खबरें अक्सर न्यूज चैनलों की सुर्खियां बनती हैं। विदेशी में बैठकर गैंगस्टर नेटवर्क का संचालन हो रहा है। भारत को अस्थिर करने वाले तत्त्वों को बैरून मुल्कों की खुलेआम हिमायत हासिल है।

अपनी तहजीब व खूबसूरती के लिए विश्वविख्यात कश्मीर घाटी को जहन्नुम में तब्दील करने का असबाब गन कल्चर की हिमायत ही बना था। सन-1990 के दशक में आतंक के तर्जुमान पाकिस्तान तथा मजहब के रहनुमाओं ने युवाओं को जन्नत में बहत्तर हूरों का जहालत भरा ख्वाब दिखाकर बंदूक उठाने के लिए ही प्रेरित किया था। नतीजतन 'कश्यप ऋषि' की तपोस्थली कश्मीर 'कलाश्निकोव राइफलों' के खौफनाक शौर से आज तक थरथर्रा रहा है। मादक पदार्थ व डंग्स के अवैध बाजार पर कब्जा जमा चुकी पाक खूफिया एजेंसी 'आईएसआई' सरहदी राज्यों में गैंगस्टर नेटवर्क को हवा देकर आतंकवाद को जीवित रखना चाहती है। बाहरी मदद से भारतीय हदूद में हथियार व असलाह गिराने के मंसूबों को अंजाम दिया जाता है। हैरत की बात है कि देवभूमि जैसे मुकद्दस नाम की शिनाख्त वाले राज्य हिमाचल प्रदेश के धरातल पर गोलीकांड जैसी कातिलाना वारदातें सरेआम हो रही हैं। बड़े महानगरों व विदेशों में फैलने वाली नशे की महामारी के जहरीले शजर पहाड़ की शांत शबनम पर बहुत पहले उग चुके हैं, मगर लूटमार, डकैती व कत्ल जैसी कई क्रूरता भरी हिंसक वारदातों का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है।

देश में कोई भी आपराधिक घटना हो तो सियासत की दर्जा-ए-हरारत बढ़ जाती है। मगर अपराध आखिर अपराध है। गुनाह का सबब बनने वाली हर बुराई की मुखाल्फत सख्त लहजे में होनी चाहिए। अराजकता का माहौल पैदा करने वाले तत्त्वों के खिलाफ सरकारों को सख्त एक्शन लेना होगा। हथियारों की नुमाइश युवाओं की शानो-शौकत है या वक्त की नजाकत, यह एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन जुर्म की दुनिया का एक बड़ा चेहरा बनने की ख्वाहिश तथा हथियार संस्कृति के बढ़ते क्रेज से समाज में खून के रिश्ते बेरहम हो चुके हैं। बहरहाल आगाज-ए-जवानी में गन कल्चर की उल्फत में डूब रहे युवाओं से अपील है कि यदि हथियारों से खेलने का शौक है तो दुनिया की सर्वोत्तम भारतीय थल सेना का हिस्सा बनें। सेना में प्रशिक्षण के साथ कई किस्म के आधुनिक हथियारों से मुखातिब होने का मौका मिलेगा। सभ्य समाज व सशक्त राष्ट्र के निर्माण के मद्देनजर युवावर्ग के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सियासी नजर-ए-करम की निहायत जरूरत है।

पुल ही तो गिरे हैं

पता नहीं इतना हंगामा काहे को बरपा है। चार-पांच पुल ही तो गिरे हैं, कोई आसमान तो नहीं गिर गया। अब पुल कैसे गिर गए, इस पर हाय तौबा मची है। नेता लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं। यहां तो उद्घाटन से पहले सरकारी भवन भी गिर जाते हैं। स्कूल की छत भी गिर जाती है। सरकारी डंगे गिर जाते हैं। हमारे रहनुमाओं के चरित्र गिर जाते हैं। उन पर चर्चा नहीं होती। सिर्फ पुल गिरने पर चर्चा हो रही है। हंगामा हो रहा है। कंट्रोवर्सी हो रही है। सदन में बहस का स्तर गिर जाए, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। देश की इकोनॉमी गिर जाए, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। बैंकों की ब्याज दरें गिर जाएं तो उस पर भी कोई ज्यादा हल्ला नहीं होता। लेकिन पुल गिरना बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। अरे भई पुल सरकार ने बनवाए हैं। ठेकों पर बनवाए हैं। ठेकेदार ने सरकार को कमीशन दिया है और कमीशन देकर ही ठेका लिया है। अब ठेकेदार ने पुल की लाइफ का ठेका थोड़ी ले रखा है। उसने पुल बना कर दिया। सरकार से पेमेंट ली। पेमेंट में से सरकार को हिस्सा दिया और फिर दूसरे पुल के टेंडर के लिए एप्लाई कर दिया। इससे ज्यादा ठेकेदार बेचारा और क्या करे? पुल से लिपट कर खड़ा रहे! जिस तरह इनसान का आपस में भाईचारा होता है, इस तरह पुलों का भी आपस में भाईचारा होता है। जब एक पुल ने दूसरे पुल को गिरते देखा होगा तो वह बहुत आहत हुआ होगा। हो सकता है डिप्रेशन में आकर उस पुल ने आत्महत्या कर ली हो। देखादेखी कुछ और पुल भी उनके दुख में डूब गए हों। आलोचकों को इसमें मानवीय एंगल देखना चाहिए। पुल क्यों गिर रहे हैं या पुलों को गिरने पर मजबूर कौन कर रहा है, इस पर भावुक होकर विचार किया जाना चाहिए। यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे के आगे बाकी सारे मुद्दे गौण हैं।

महंगाई बढ़ जाए, कोई बात नहीं, रूखी सूखी खा लेंगे। भ्रष्टाचार बढ़ जाए, कोई बात नहीं, आंखों पर पट्टी बांध लेंगे। बेरोजगारी बढ़ जाए, कोई बात नहीं, थोड़ा ठगी ठोरी कर लेंगे। कानून व्यवस्था का जनाजा उठ जाए, कोई बात नहीं। ऐसा पहले भी होता आया है और बाद में भी होता रहेगा। लेकिन पुलों का मामला गंभीर मामला है। गुस्से में, नाराजगी में और हताशा में अगर पुल गिरने लगे तो फिर देश की प्रगति की रफ्तार थम जाएगी। इसलिए पुलों की संवेदनाओं को समझना होगा। सदाचारी नेताओं से हम पुलों का उद्घाटन करवाएंगे तो पुल कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। लेकिन ऐसे वैसे नेताओं के हाथ में फीता काटने की कैंची थमा देंगे तो फिर पुल भी शर्मिंदगी फील करेंगे न। कई बार पुल किसी ने मंजूर करवाया होता है और उद्घाटन करने कोई दूसरा पहुंच जाता है। बेचारे पुल उस वक्त तो अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पाए, लेकिन भीतर ही भीतर गुस्से की आग जलती रहती है और एक दिन वे ठंडे पानी में डुबकी लगा लेते हैं। अब पुल गिर रहे हैं और सरकार जांच बैठा रही है। गिरे हुए पुलों का बयान कौन दर्ज करेगा। पुल तो इस व्यवस्था के हाथों शर्मिंदा हैं। जांचकर्ता भी इसी व्यवस्था का हिस्सा हैं। जांचकर्ताओं ने भ्रष्ट लीडरों को भी बचाना है, अफसरों को भी बचाना है, ठेकेदार से भी मालपानी खाना है और फिर अपनी रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट फिर सरकारी गलियारों में गायब हो जानी है। पुलों को पता भी नहीं चलना कि दोष किसके सिर मढ़ा गया। बात आई-गई हो जानी है।

गुरमीत बेदी

शेयर बाजार का पर्सनल इंडीकेटर

परिवहन विशेष न्यूज

जैसे-जैसे मार्केट चढ़ता है आइपीओ की राह आसान हो जाती है और इन्वेस्टमेंट बैंकरों के लिए ये और भी ज्यादा आकर्षक बन जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब इन्वेस्टमेंट बैंकर ऐसे कारोबारों के मालिकों को भी लुभाने के लिए बेचैन हो जाते हैं जिन्हें मार्केट में उतरने की जरूरत नहीं होती। बेशक मैं गलत भी हो सकता हूं। हर चीज कभी न कभी पहली बार होती ही है।

नई दिल्ली। मुझे आपको ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि हाल के कुछ सप्ताह में शेयर बाजारों में आए फेन (झाग) को दिखाने वाला इंडीकेटर हरकत में आ गया है। क्या आप ये सुन कर हैरान हुए? मुझे थोड़ा पीछे जाकर इस बात को खुलकर समझाना चाहिए।

क्या भारतीय इक्विटी मार्केट अब बीयर के ऐसे मग की तरह दिखने लगे हैं जिसे बहुत तेजी से भरा गया है? क्या ऊपर जमा हुआ फेन या झाग जल्दी ही बैठ जाएगा या यूं ही बना रहेगा? कोई कैसे पता लगाए कि क्या मार्केट के इस व्यवहार का कुछ ठोस और टिकाऊ आधार है?

वैल्यूएशन, लाभ का बढ़ना आदि ऐसे कई सीरियस इंडीकेटर हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर इन सवालों का जवाब देने के लिए किया जाता है। कुछ हल्के-फुल्के मिजाज वाले इंडीकेटर भी हैं, जो मजाक जैसे लगेंगे पर असलियत में अच्छा करते हैं। मिसाल के तौर पर, जब शेयर मार्केट के इंडीकेटरों के बढ़ने की हेडलाइन गुलाबी अखबारों के बजाय सफेद अखबारों में आने लगती हैं, तो शेयर की कीमतें बढ़ सकती हैं।

मेरे पास एक पर्सनल इंडीकेटर भी है जो शेयर मार्केट में आए इस फेन को दिखाए और ये पिछले दो दशकों में अचूक रहा है। जब इन्वेस्टमेंट बैंकर वैल्यू रिसर्च का आइपीओ लाने के लिए मुझे काल करना शुरू करते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि इक्विटी मार्केट बहुत गर्मा गया है।

जैसे-जैसे मार्केट चढ़ता है, आइपीओ की राह आसान हो जाती है और इन्वेस्टमेंट बैंकरों के लिए ये और भी ज्यादा आकर्षक बन जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है, जब इन्वेस्टमेंट बैंकर ऐसे कारोबारों के मालिकों को भी लुभाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, जिन्हें मार्केट में उतरने की जरूरत नहीं होती। बेशक, मैं गलत भी हो सकता हूं। हर चीज कभी न कभी पहली बार होती ही है।

मैं आपसे अपने सभी स्टाक और इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचने की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर मुझे काल कर रहे हैं। हालांकि, ये 'मजेदार' किस्म के मार्केट इंडीकेटर चाहे जो कुछ भी दिखाएं, इसके बावजूद, ये समय कुछ सावधान रहने का है।

इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में

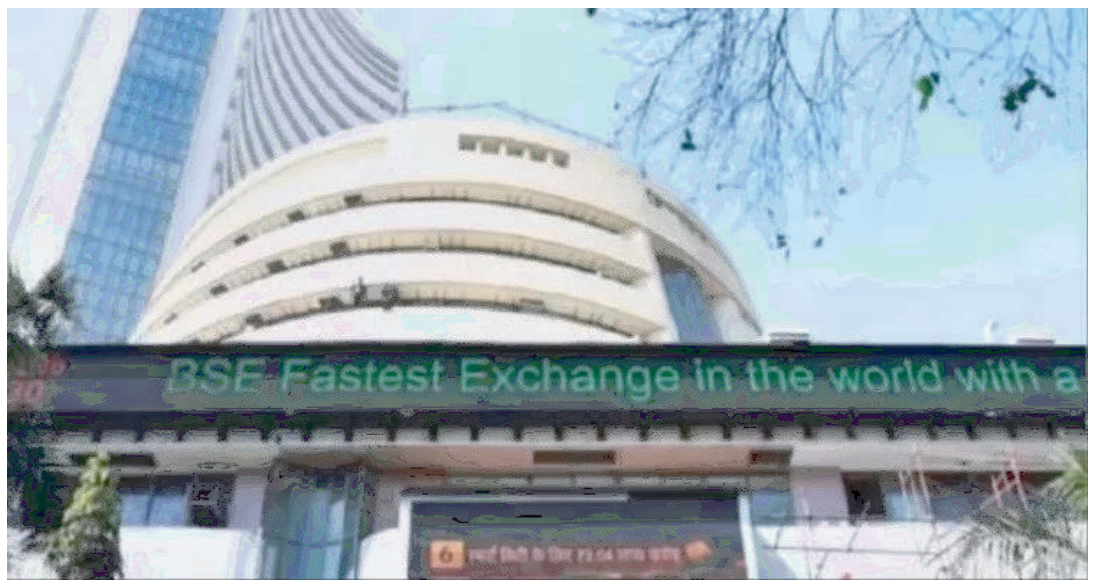

गिरावट आएगी ही या अभी मिलने वाला हर मुनाफा एक भ्रम है। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने गजब का लचीलापन और ग्रोथ की क्षमता दिखाई है। हालांकि, अनुभवी निवेशक जानते हैं, मार्केट शायद ही कभी सीधी रेखा में चलते हों। तेजी के दौर के बाद अक्सर मार्केट की परख होती है।

याद रखें, सबसे अच्छे निवेश के फैसले अक्सर तब लिए जाते हैं जब आप ज्यादा लोगों की भावनाओं के ज्वार के खिलाफ तैर रहे होते हैं। इसलिए, जब मार्केट ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं, तब सावधानी की एक स्वस्थ खुराक के साथ तेजी के उत्साह को काबू में रखना अक्लमंदी होती है।आइए देखें कि इस बात क्या मतलब है। ये बढ़े हुए आशावाद का दौर है जिसमें निवेशकों को अपने एसेट एलोकेशन को लेकर सोचना चाहिए।

विविधता पर ध्यान देना चाहिए और बुनियादी बातों के मुताबिक अपना पोर्टफोलियो दुरुस्त कर लेना चाहिए। एक औसत निवेशक के लिए, चाहे वो सीधे स्टाक में निवेश करता हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड का मुरीद हो, उसे अपने पोर्टफोलियो में नाटकीय बदलाव करने या एसेट बेचने की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है।

इसके बजाय, ये एसेट एलोकेशन और निवेश के लक्ष्यों पर दोबारा नजर डालने और उनका पुनर्मूल्यांकन करने का एक मौका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बड़े रिस्क और बड़े मुनाफे वाले स्टाक या अग्रेसिव इक्विटी फंड्स में बहुत ज्यादा निवेश कर रहे हैं? स्टाक निवेशकों को उनके एलोकेशन को ज्यादा स्थिर रखने वाले और वैल्यू-ओरिएंडेट स्टाक में निवेश के बारे में सोचना चाहिए।

म्यूचुअल फंड निवेशक, ज्यादा स्थिरता वाले लार्ज-कैप या बैलेंस्ड फंड पर विचार कर सकते हैं। अपने इमरजेंसी फंड पर भी फिर से सोच-विचार करना सही होगा। मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय, कैश ज्यादा होने से वित्तीय और भावनात्मक सुरक्षा मिल सकती है।

इस हफ्ते कैसी रहेगी बाजार की चाल, किस सेक्टर पर रखना चाहिए निवेशकों को नजर

इस हफ्ते शेयर बाजार ने नए रिकॉर्ड बनाया है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में आईटी शेयरों में आई शानदार तेजी ने बाजार को नए उच्चतम स्तर को छू लिया। अब सोमवार से शुरू होने वाले कारोबारी हफ्ते में बाजार की चाल कैसी रहेगी? निवेशकों को किन शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। आइए इस रिपोर्ट में इसके बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। शेयर बाजार के निवेशकों को आगामी हफ्ते में बाजार की चाल पर ध्यान देना होगा। 15 जुलाई 2024 (सोमवार) से शुरू होने वाले हफ्ते में बाजार केवल 4 दिन के लिए ही खुला रहेगा। मोहरम के मौके पर 17 जुलाई 2024 (बुधवार) को बाजार के स्टॉक एक्सचेंज में कोई शेयर की खरीद-बिक्री नहीं होगी।

ऐसे में एनलिस्ट का कहना है कि निवेशकों को आगामी हफ्ते में जारी होने वाले कंपनी के तिमाही नतीजों पर नजर बना कर रखनी चाहिए। कंपनी के शेयरों के साथ फॉरेन इन्वेस्टर का भी शेयर मार्केट में काफी अहम रोल है।

आगामी हफ्ते में ये फैक्टर्स निभाएंगे अहम रोल

सोमवार 15 जुलाई को जून महीने के खुदरा महंगाई दर (WPI inflation data) का एलान होगा। शुक्रवार को जारी रिटेल महंगाई दर के अनुसार जून में खान-पान की चीजें महंगी हो जाने की वजह से सीपीआई 5 फीसदी के ऊपर पहुंच गया। ट्रेडर्स का कहना है कि बाजार की ट्रेडिंग पर खुदरा महंगाई दर का भी असर पड़ेगा।

इस हफ्ते HDFC Life Insurance Company, Bajaj Auto, BPCL, JSW Steel, Asian Paints, Infosys, and Reliance Industries जैसे कई दिग्गज कंपनी अपने तिमाही नतीजों का एलान करेंगी। कंपनी के तिमाही नतीजों का सीधा असर स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलेगा।

एचसीएल के शेयरों पर रहेगा फोकस

बीते दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज (HCL Tech) ने जून तिमाही के नतीजों की घोषणा की थी। अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 20.4 फीसदी बढ़ गया है। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू में भी 3 से 5 फीसदी की बढ़त हुई है। ऐसे में सोमवार को कंपनी के शेयर फोकस में रहेंगे। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा हमें उम्मीद है कि चालू कमाई के मौसम के कारण स्टॉक-विशिष्ट चालें जोर पकड़ेंगी। वास्तव में अच्छी कमाई होने के कारण आईटी सेक्टर फोकस में रहेगा।

स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 750 करोड़ रुपये खर्चेगी सरकार, जानिए क्या है प्लान

परिवहन विशेष न्यूज

पहल का उद्देश्य 750 करोड़ रुपये की कैटेगरी-II वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) की स्थापना के माध्यम से भारत के कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में बोलते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू ने इस कोष की क्षमता पर जोर दिया। आइए जानते हैं कि इसको लेकर पूरा प्लान क्या है।

नई दिल्ली। सरकार कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए 'स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष' (AgriSURE) शुरू करने जा रही है। शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस कोष के माध्यम से निवेश क्षेत्र-विशिष्ट होगा और ऋण वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के साथ-साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्ट-अप को प्रत्यक्ष इक्विटी सहायता भी दी जाएगी।

ये है विजन

इस पहल का उद्देश्य 750 करोड़ रुपये की कैटेगरी-II वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) की स्थापना के माध्यम से भारत के कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना है। यह कोष विशेष रूप से कृषि मूल्य श्रृंखला में उच्च जोखिम, उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों को लक्षित करते हुए इक्विटी और ऋण दोनों सहायता प्रदान करेगा।

यह घोषणा शुक्रवार को मुंबई में नाबार्ड मुख्यालय में प्री-लॉन्च स्टेकहोल्डर मीट में की गई। इस कार्यक्रम में वित्तीय संस्थानों, निवेशकों, एआईएफ प्रबंधकों और कृषि स्टार्टअप सहित प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया।

अजीत कुमार साहू ने क्या कहा?

कार्यक्रम में बोलते हुए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू ने इस कोष की क्षमता पर जोर दिया, जिससे एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके जो नवीन दृष्टिकोणों के माध्यम से कृषि क्षेत्र के लिए वित्तपोषण को बढ़ाए, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को लाभ हो।

कार्यक्रम के दौरान, नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी के वी ने तकनीकी नवाचारों के माध्यम से कृषि में विकास के अगले स्तर को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहयोग की आवश्यकता पर बात की।

टमाटर की कीमतों को लेकर आया नया अपडेट, सरकारी अधिकारी ने खुद बताया कितने दिनों में कम होंगे दाम

देश में लोग अभी महंगे टमाटर के मार से जूझ रहे हैं। टमाटर की कीमतों में नरमी का आम जनता भी इंतजार कर रही है। अब टमाटर की कीमतों को लेकर नया अपडेट सामने आया है। सरकारी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को जानकारी दी है कि कब से टमाटर के दाम में नरमी आएगी। आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। देश के कई क्षेत्र में टमाटर के दाम 100 रुपये के पार पहुंच गए हैं। आम जनता ने महंगे टमाटर को लेकर काफी परेशान है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने टमाटर खाना ही बंद कर दिया है। आम जनता टमाटर की कीमतों में नरमी का इंतजार कर रहे हैं।

टमाटर की कीमतों को लेकर नया अपडेट सामने आया है। सरकारी अधिकारी ने बताया कि आने वाले हफ्ते में देश की राजधानी दिल्ली में टमाटर के दाम में नरमी आएगी। हालांकि अभी राजधानी दिल्ली में टमाटर 75 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई है। दक्षिणी राज्यों से आने वाले टमाटर सप्लाई में इन्प्रूवमेंट होने के बाद टमाटर की कीमतों में नरमी आएगी।

सरकारी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि आलू और प्याज की कीमतों में भी जल्द नरमी देखने की उम्मीद है। सप्लाई में कमी आने की वजह से इनके दाम बढ़े थे।

दिल्ली समेत कई शहरों में आलू, टमाटर, प्याज के दाम आसमान को छू रहे हैं। हीटवेव और भारी बारिश की वजह से इनकी सप्लाई सही से नहीं हुई और कई जगह पर फसल भी खराब हो गए। सही मात्रा में प्रोडक्शन न होने की वजह से और आपूर्ति की कमी की वजह से इनके दाम बढ़ गए थे।

नई दिल्ली में टमाटर की कीमत बढ़कर 75 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, लेकिन अगर आगे भारी बारिश की वजह से सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ता है तो इनकी कीमतों में नरमी आने की संभावना है।

टमाटर की अभी क्या है कीमत

मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 12 जुलाई 2024 को दिल्ली में टमाटर की खुदरा कीमत 75 रुपये प्रति किलोग्राम थी। यह एक साल की अवधि में 150 रुपये प्रति किलोग्राम थी। वहीं आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई में टमाटर की कीमत 83 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत 80 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य के अनुसार 12 जुलाई 2024 को टमाटर के दाम 65.21 रुपये प्रति किलोग्राम था, जबकि पिछले साल यह 53.36 रुपये प्रति किलोग्राम था।

अभी दिल्ली को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से टमाटर की सप्लाई मिल रही है। अधिकारी ने बताया कि जैसे ही आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से हाइब्रिड टमाटर की सप्लाई राष्ट्रीय राजधानी में होने लगेंगी इनकी कीमतों में कमी होने लगेंगी।

क्या सरकार कर रही है कोई प्लानिंग

इस साल सरकार टमाटर की सब्सिडी वाली बिक्री की योजना शुरू नहीं कर रही है। पिछले साल सरकार ने टमाटर की सब्सिडी वाली बिक्री योजना लागू किया था। आपको बता दें कि पिछले साल टमाटर की कीमत 110 रुपये प्रति किलोग्राम से ज्यादा हो गई थी। ऐसे में टमाटर की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया था।

सरकारी अधिकारी ने विश्वास जताया कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से सप्लाई में सुधार होने के बाद 1-2 सप्ताह के भीतर ही टमाटर की कीमत सामान्य हो जाएंगी।

अधिकारी ने यह भी बताया कि भारत के पास 283 लाख टन आलू भंडारित है। यह पिछले वर्ष की तुलना में कम उत्पादन के बावजूद घरेलू मांग को पूरा करने के लिए काफी है। महाराष्ट्र के थोक बाजारों में प्याज की कीमतें कम हो गई हैं, सितंबर में नई फसल के आने के साथ प्याज की कीमतों में और गिरावट आने की उम्मीद है।

भारी बारिश की वजह से टमाटर, आलू, प्याज और हरी सब्जियों के सप्लाई पर प्रभाव पड़ा था, जिस वजह से इनके दाम चढ़ गए। सरकार आने वाले हफ्तों में इनकी कीमतों में नरमी को लेकर आशावादी बनी हुई है। अगर मौसम की स्थिति प्रतिकूल रही तो जल्द ही टमाटर, आलू, प्याज की कीमतों में गिरावट आएगी।

आम बजट में किसानों के लिए हो सकते हैं कई एलान, पीएम किसान योजना की राशि बढ़ोतरी के साथ इन घोषणाओं की है उम्मीद

परिवहन विशेष न्यूज

23 जुलाई 2024 को आम बजट पेश होने वाला हैं। इस बजट से किसानों को कई उम्मीदें हैं। सरकार एग्री-सेक्टर में विकास के लिए कई बड़े एलान कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में पीएम किसान योजना की राशि में इजाफा कर सकती है। इसके अलावा किसान की इनकम में बढ़ोतरी के लिए भी एलान हो सकता है।

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 (मंगलवार) को आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम जनता के साथ किसानों को भी कई उम्मीदें हैं।

किसानों को बजट से क्या उम्मीद है? अगर इसकी बात करें तो सबसे पहला जिक्र होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme) के बारे में, जी हां, किसानों को उम्मीद है कि इस बजट में सरकार पीएम किसान योजना में मिलने वाली किस्त राशि में इजाफा कर सकती है।

आइए, जानते हैं कि बजट 2024 (Budget 2024) को लेकर किसानों को क्या-क्या उम्मीदें हैं।

बढ़ सकती है किस्त की राशि

सरकार द्वारा किसानों को वित्तीय लाभ देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) शुरू की गई थी। इस योजना में सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। पिछले महीने सरकार ने पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी की थी। आपको बता दें कि वर्तमान में किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये किस्त के तौर पर आते हैं।

अब किसान योजना की किस्त की राशि में रिवीजन का इंतजार कर रहे हैं। एक्सपर्ट ने भी पीएम किसान योजना में मिल रही 6,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये करने का डिमांड किया है।

इस साल अप्रैल में हुई एक चर्चा में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार का फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज्यादा है। सरकार का फोकस पीएम किसान योजना पर हैं। उन्होंने कहा था कि छोटे किसानों को भी इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि, निर्मला सीतारमण ने योजना की राशि बढ़ाने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी थी।

इन चीजों पर भी है फोकस

कर्ज माफी

> सरकार किसानों की इनकम में बढ़ोतरी के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं में से एक पीएम किसान योजना भी है। हालांकि, इन स्कीम्स से किसानों की इनकम में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। सरकार ने अभी तक किसानों की इनकम को दोगुना करने के टारगेट को हासिल नहीं किया है। आपको बता दें कि अगर फसल की एमएसपी बढ़ती है तो किसानों की इनकम बढ़ने में मदद मिलती है।

कुछ समय पहले तेलंगाना सरकार ने किसानों का कर्ज माफ को लेकर प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड और पंजाब की सरकारों ने भी कर्ज माफी को लेकर अपील की थी। ऐसे में उम्मीद है कि बजट में कर्ज माफी को लेकर कोई बड़ा एलान हो सकता है। हालांकि, कर्ज माफी हो जाने के बाद भी किसानों की इनकम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए सरकार कोई एलान कर सकती है।

किसानों की इनकम

सरकार किसानों की इनकम में बढ़ोतरी के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं में से एक पीएम किसान योजना भी है। हालांकि, इन स्कीम्स से किसानों की इनकम में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। सरकार ने अभी तक किसानों की इनकम को दोगुना करने के टारगेट को हासिल नहीं किया है। आपको बता दें कि अगर फसल की एमएसपी बढ़ती है तो किसानों की इनकम बढ़ने में मदद मिलती है।

ऐसे में उम्मीद है कि बजट में किसानों की इनकम को लेकर सरकार कोई एलान कर सकते हैं।

किसानों की वित्तीय स्थिति

देश के किसानों की वित्तीय स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। ऐसे में किसानों के लिए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) या क्रॉप इंश्योरेंस जैसे कई कदम उठा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में किसानों को सालाना 4 फीसदी के ब्याज पर लोन मिलता है।

वहीं, क्रॉप इंश्योरेंस में किसानों को लाभ होता है। हालांकि, इन दोनों स्कीम्स से किसानों की वित्तीय स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में किसानों की वित्तीय स्थिति की सुधार के लिए सरकार द्वारा कोई एलान हो सकता है।

नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

देश में हर सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं हो रहा है। बजट में एग्री सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी को लेकर कोई एलान होने की उम्मीद है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार एग्री-सेक्टर में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कोई नया प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं।

चुनावी नतीजों से गदगद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, बोली- पूरे देश में भाजपा के खिलाफ माहौल

सात राज्यों के 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव नतीजों पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की सहयोगी और पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी काफी गदगद हैं। इस कड़ी में उन्होंने अपनी मुख्य विरोधी और केंद्र की भाजपा पर जमकर निशाना साधा है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को दावा किया कि विधानसभा उपचुनाव नतीजों से ये साफ हो गया है कि देश भर में भाजपा के खिलाफ माहौल है। बता दें कि सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों को 10 सीटों पर जीत मिली है। वहीं भाजपा को मात्र दो विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है। जबकि बिहार के पूर्णिया जिले की रूपौली विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। इंडिया का वोट शेयर 51 फीसदी- ममता वहीं ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि एनडीए को मात्र 46 प्रतिशत वोट मिला है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया का वोट शेयर 51 फीसदी है। 13 विधानसभा सीटों की बात करें तो पश्चिम बंगाल की चार, तीन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की दो और पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु की एक-एक सीटों पर मतदान हुआ था।

जीत के लिए जनता का जताया आभार

पश्चिम बंगाल में सभी चार सीटों पर टीएमसी की जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़कर अन्य राज्यों में हुए उपचुनावों में भी भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। बता दें कि मुंबई से लौटने पर एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से कहा, पूरे भारत में रुझान भाजपा के खिलाफ है। वहीं यह पूछे जाने पर कि क्या यह इस बात का संकेत है कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, इस पर ममता बनर्जी ने कहा, रुझान बहुत स्पष्ट है, यहां तक कि पहले का जनादेश (लोकसभा चुनाव का) भी एनडीए के पक्ष में नहीं था।

'भाजपा ने फिर से शुरू किया एजेंसी राज'

भाजपा लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल में अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी। उन्होंने कहा, जनादेश उनके खिलाफ है और अब उन्होंने फिर से एजेंसी राज शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने भाजपा से रायगंज, बागदा और राणाघाट दक्षिण सीटें छीन लीं और कोलकाता में मानिकतला सीट बरकरार रखी। उन्होंने कहा, रायगंज और मानिकतला में चुनावों का राजनीतिक महत्व है। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि मानिकतला में पार्टी उम्मीदवार सुप्ती पांडे की 62 हजार से अधिक मतों से जीत बहुत अच्छी थी।

उपचुनाव के नतीजों को लेकर भाजपा बरसीं महुआ मोइत्रा

इधर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उपचुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके 'एजेंसी राज' की 'हार का सिलसिला' जारी है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक को सात राज्यों में हुए उपचुनावों में 13 विधानसभा सीटों में से 10 पर जीत मिली है। मोइत्रा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इसलिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में 4/4 विधानसभा उपचुनाव जीते हैं, जबकि इंडिया ने राष्ट्रीय स्तर पर 10/13 जीते हैं। भाजपा और उसके एजेंसी राज की हार का सिलसिला जारी है। इस दौरान उन्होंने पोस्ट में प्रधानमंत्री को टैग करते हुए कहा, लोग कह रहे हैं 'तुमसे न हो पाएगा' नरेंद्र मोदी।

अनंत-राधिका के शुभ आशीर्वाद समारोह में पहुंचे पीएम मोदी;दोनों ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। अपने मुंबई दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए। इसका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी के 'जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर' में पहुंचने पर दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी ने पत्नी नीता अंबानी समेत आगे बढ़कर उनका ग्रैंड वेलकम किया। इसके बाद आकाश और अनंत ने दोनों ने पांव छूकर प्रधानमंत्री के पैर छुए। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे।

इस दौरान, पीएम मोदी ने मुकेश के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी नवविवाहिता राधिक मर्चेंट को शादी के पवित्र बंधन में बंधने की शुभकमानाएं व आशीर्वाद दिया।

बता दें कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के कार्यक्रम बीते सात महीनों से चल रहे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने शुक्रवार (12 जुलाई) को सात फेरे लिए। इस शाही समारोह में देश-दुनिया की कई चर्चित हस्तियां शामिल हुईं। खेल, बिजनेस, मनोरंजन और राजनीति की दुनिया के लोकप्रिय चेहरे शादी का हिस्सा बने।

अनंत राधिका के आशीर्वाद समारोह में शामिल होने वाले लोगों में तकरीबन पूरा बॉलीवुड शामिल था। इसमें मुख्य रूप से अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और रणबीर कपूर थे। उनके अलावा, जान्हवी कपूर को रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ देखा गया तो वहीं केएल राहुल अथिया शेट्टी का हाथ थामे पहुंचे।वहीं खेल जगत से क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या और सूर्यकुमार यादव के साथ ही बैडमिंटन चैंपियन सानिया मिर्जा भी शामिल हुईं। सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी भी अंबानी परिवार के शुभ आशीर्वाद रस्म में शामिल हुए। सचिन तेंदुलकर ने ब्लैक आउटफिट कैरी किया तो वहीं उनकी पत्नी खूबसूरत पिंक साड़ी में नजर आईं।

शादी में शामिल होने वाले राजनेताओं में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी देवेंद्र फड़नवीस और अजीत पवार, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल और शिव सेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे, राकांपा (सपा) सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस नेता कमल नाथ शामिल थे। रिसेप्शन में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस भी शामिल हुए। वहीं वैश्विक नेताओं में पूर्व ब्रिटिश प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर और बोरिस जॉनसन भी शामिल हुए।

इस कार्यक्रम में द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ ही स्वामी रामभद्राचार्य भी शामिल हुए। उनके अलावा, फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उनके डिप्टी पवन कल्याण भी उपस्थित थे।

उपचुनाव में जीत से मिली आईएनडीआईए को नई ऊर्जा, बजट सत्र में दिखेगा असर; अयोध्या के बाद इस सीट की होगी चर्चा

सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के चुनाव नतीजों ने इंडी गठबंधन को नई ऊर्जा प्रदान की है। लोकसभा चुनाव में मजबूती से उभरे विपक्ष को अब सरकार पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया है। चुनाव नतीजों से कांग्रेस की उम्मीदों को बल मिला है तो वहीं बंगाल में टीएमसी और मजबूत हुई है।

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में मजबूत विपक्ष के रूप में उभरे आईएनडीआईए गठबंधन को सात राज्यों के उपचुनाव में मिली बड़ी कामयाबी ने राजनीतिक दमखम दिखाने का एक और मौका दे दिया है। सात राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 10 सीटें जीत कर विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए ने संसद के आगामी बजट सत्र से ठीक पहले मोदी सरकार पर सियासी दबाव बढ़ाने की बड़ी खुराक हासिल कर ली है जिसका सियासी असर सत्र के दौरान दिखना लगभग तय है।

विपक्ष को ऊर्जा मिलनी तय

विशेषकर लोकसभा चुनाव में फैजाबाद-अयोध्या सीट के बाद उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा की हार से विपक्ष को उस पर हमले के लिए नई उर्जा मिलनी तय है। बदरीनाथ सीट जीतने वाली कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल करने को जनता द्वारा नकारे जाने की बात कह भाजपा की वैचारिक सियासत पर प्रहार जारी रखने के इरादे साफ भी कर दिए।

कांग्रेस की उम्मीदों को मिला बल

उपचुनाव परिणामों की खास बात यह भी है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों ने जहां अपने गढ़ को बचाए रखा वहीं कुछ राज्यों में भाजपा-एनडीए गठबंधन को झटका भी दिया है। आईएनडीआईए का नेतृत्व कर रही कांग्रेस के लिए उपचुनाव के नतीजे विशेष रूप से राजनीतिक उम्मीद जगाने वाले हैं क्योंकि दो पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जहां उसका भाजपा से सीधा मुकाबला है वहां पार्टी ने दमदार प्रदर्शन किया है।

कांग्रेस को मिला हमला करने का मौका

हिमाचल की तीनों सीटों निर्दलीय के पास थी जिसमें से कांग्रेस ने दो उनसे छीन ली है। उत्तराखंड में भी पार्टी ने बदरीनाथ की प्रतिष्ठित सीट समेत दोनों सीटें उपचुनाव में जीती है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की शिकस्त ने कांग्रेस को उस पर हमले का एक और मौका दे दिया है।

क्यों अहम हैं हिमाचल और उत्तराखंड उपचुनाव?

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने धर्म को राजनीतिक औजार बनाने की भाजपा की सियासत को जनता द्वारा खारिज करने की बात इसकी शुरूआत करने में देरी भी नहीं की। हिमाचल और उत्तराखंड के उपचुनाव नतीजे कांग्रेस के लिए इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हैं कि अभी हुए लोकसभा चुनाव में इन दोनों सूबों की नौ लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का सफाया हो गया था। उत्तराखंड की पांचों सीटें तो हिमाचल की चारों सीटें भाजपा के खाते में आयी थी।

हंगामेदार होगा बजट सत्र

18वीं लोकसभा में उभरे मजबूत विपक्ष की झलक पहले सत्र में ही दिख गई थी जब नीट पेपर लीक धांधली के मुद्दे पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। राष्ट्रपति अभिभाषण पर बहस और पीएम मोदी के इस पर जवाब के दौरान भी सरकार और विपक्ष के आक्रामक तेवरों ने दोनों सियासी खेमों के बीच कड़वाहटों के दौर की बुनियाद रख दी थी।

उपचुनाव परिणामों के बाद विपक्ष का हौसला अब कहीं ज्यादा रहेगा और ऐसे में 22 जुलाई से शुरू हो रहे बजट सत्र में इसका वृहद स्वरूप सामने आएगा यह लगभग तय है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की उपचुनाव पर आयी प्रतिक्रियाओं ने भी इस ओर इशारा कर दिया है।

बंगाल में कायम है टीएमसी का दबदबा

उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल की चारों सीटें जीतकर अपना सियासी दबदबा बनाए रखने का संदेश दिया है। लोकसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी के बाद टीएमसी प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इन नतीजों ने भाजपा पर प्रहार के लिए दोहरी ऊर्जा दे दी है और बिना देरी किए मोदी सरकार की स्थिरता पर सवाल उठा दीदी ने इसमें तनिक भी देरी नहीं की। बंगाल के अपने गढ़ पर वर्चस्व कायम रखते हुए ममता ने आईएनडीआईए के भीतर भी अपनी स्थिति को और मजबूती दी है।

स्वामी तेजानन्द महाराज का किया भव्य स्वागत

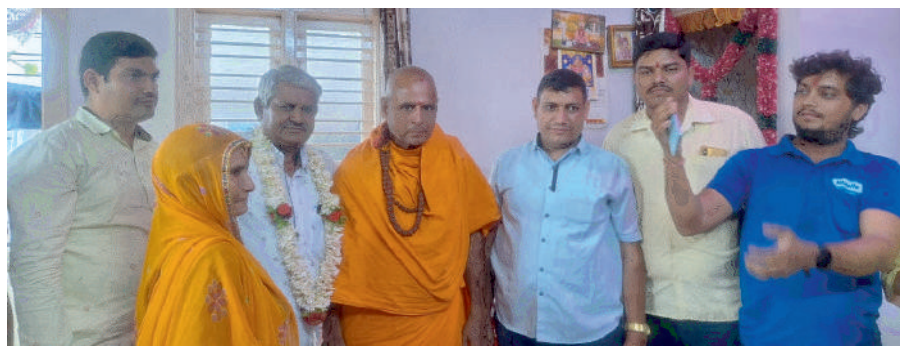

परिवहन विशेष न्यूज

बेंगलूरू: शुक्रवार को सुबह 5 बजे के. दुर्गाराम ओमप्रकाश s/o कन्नाराम परिहार के बेंगलूरू शहर के बेग बेगूर में स्थित ग्रहप्रवेश कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में तामीलनाडु पॉन ब्रोकर ऐवम ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष वह श्री लिलडीया भेरुजी आईमाताजी सोऽहम आश्रम पेरीयपालीयम के संचालक स्वामी तेजानन्द महाराज उपास्थित होकर के. दुर्गाराम परिहार के परीवार को शुभ आर्शीवाद प्रदान किया। इस कार्यक्रम में मुख्यअतिथि के रुप पहंचे स्वामी तेजानन्द महाराज का दुर्गाराम परिहार के परिवार द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में हितेश परिहार, केलाश परीहार, श्रीमती डी.पुजादेवी पी. सत्यनारायण परिहार, किशनलाल परिहार, हनूमान परिहार भंवरलाल मुलेवा, जयराम मुलेवा, जोगाराम सीरवी, कन्नाराम सीरवी, भोमाराम सीरवी, भानाराम गेहलोत एवं दुर्गाराम परिहार के परीवार के सभी सदस्य मौजुद थे। इस कार्यक्रम मे पेरीयपालीयम श्री लिलडीया भेरुजी आईमाताजी सोऽहम आश्रम के संचालन के लिए श्री दुर्गारामजी परिहार के परीवार कि तरफ सु 5100/रुपये कि सहयोग राशि आश्रम के संचालक स्वामी तेजानन्द को सुपुर्द कि गई।

गुजरात पहुंचा खतरनाक वायरस! दिमाग में सूजन के बाद चली जाती है जान; चार बच्चों की मौत से हड़कंप

गुजरात में चार बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया है। आशंका है कि इन बच्चों की मौत वायरस की वजह से हुई है। अभी राजस्थान के दो बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। ये दोनों बच्चे भी वायरस से संक्रमित लग रहे हैं। गुजरात के स्वास्थ्य अधिकारियों ने राजस्थान के अधिकारियों को मामले से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है।

अहमदाबाद। गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में चांदीपुरा वायरस का संक्रमण फैला है। गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में चांदीपुरा वायरस के संक्रमण से चार बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि वायरस की पुष्टि अभी नहीं हुई है। दो बच्चे गंभीर रूप से बीमार हैं। हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में दोनों बच्चों का इलाज चल रहा है।

चांदीपुरा वायरस से बुखार होता है, जिसके लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। इससे मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। यह वायरस मच्छरों, मक्खियों, कीट-पतंगों द्वारा फैलता है। दरअसल, महाराष्ट्र के नागपुर के चांदीपुर गांव में वर्ष 1966 में 15 साल तक के बच्चों की मौत होने लगी थी। पता चला कि मौतें वायरस से हुईं। तभी से इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस पड़ गया।

साबरकांठा के मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी राज सुतारिया ने बताया कि सभी छह बच्चों के रक्त के नमूने की पुष्टि के लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआइवी) भेजे गए हैं। नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में 10 जुलाई को चार बच्चों की मौत के बाद इस अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञों को संदेह कि इन बच्चों की मौत चांदीपुरा वायरस के कारण हुई।

सहायक प्रवर्तन अधिकारी कैसे बनें? : विजय गर्ग

सहायक प्रवर्तन अधिकारी - जैसा कि पद के पदनाम से संकेत मिलता है कि एक सहायक प्रवर्तन अधिकारी की जिम्मेदारी विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों का बार-बार दौरा करना और निरीक्षण करना और देश के कानूनों को लागू करना है। सहायक प्रवर्तन अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे उन लोगों की तलाश करें जो बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, और उन्हें अपने संबंधित विभाग प्रमुखों के ध्यान में लाएँ ताकि उन्हें नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया जा सके। विभागों के कामकाज के लिए बनाई गई नीतियों के अनुरूप काम करें। सहायक प्रवर्तन अधिकारी बनने के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित लिखित और मौखिक परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ताकि इतने सारे उम्मीदवारों में से केवल कुछ सक्षम लोगों का ही चयन किया जा सके। सहायक प्रवर्तन अधिकारी बनने के लिए योग्यता 1. शैक्षिक योग्यता सहायक प्रवर्तन अधिकारी इंस्पेक्टर बनने के लिए पात्र होने के लिए किसी भी स्ट्रीम से स्नातक होना चाहिए। 2. उम्र उम्मीदवार की आयु परीक्षा के वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष होनी चाहिए और उस तिथि को 27 वर्ष की आयु नहीं होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। भारत सरकार और रक्षा सेवा कार्मिक के तहत काम करने वाले कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के पक्ष में ऊपरी आयु सीमा में भी छूट दी गई है। सहायक प्रवर्तन अधिकारी कैसे बनें? सहायक प्रवर्तन अधिकारी बनने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगाः स्टेप 1 पहले कदम के रूप में, उम्मीदवार को आम तौर पर अप्रैल महीने में प्रकाशित होने वाले रोजगार समाचार पत्र से आवश्यक जानकारी के साथ ₹आवेदन पत्र₹ प्राप्त करना होगा। भरे हुए आवेदन पत्र को बताए अनुसार क्षेत्रीय केंद्रों पर भेजा जाए। नोटः नियमों और पाठ्यक्रम के संबंध में प्रासंगिक विवरण के साथ परीक्षा की अधिसूचना अप्रैल महीने में 'रोजगार समाचार'/'रोजगार समाचार', 'भारत का राजपत्र' और देश के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। चरण दो प्रारंभिक परीक्षा मई या जून के महीने में, उम्मीदवारों को दो पेपर वाली ₹प्रारंभिक परीक्षा₹ देनी होगी। कागजात चालू हैंः प्रश्न चिह्नों की विषय संख्या समय भाग ए 1.सामान्य बुद्धि और सामान्य जागरूकता 100 100 2 घंटे। भाग बी 2. अंकगणित 100 100 2 घंटा। ध्यान देंः यह परीक्षा केवल अंतिम परीक्षा के लिए एक योग्यता परीक्षा है और इस परीक्षा में प्राप्त अंक अंतिम परिणाम बनाने में नहीं जोड़े जाते हैं। चरण 3 मुख्य परीक्षा जिन उम्मीदवारों को ₹प्रारंभिक परीक्षा₹ में योग्य घोषित किया जाता है, उन्हें अंतिम परीक्षा देनी होती है। अंतिम परीक्षा में दो भाग होते हैं। भाग ए लिखित परीक्षा का होगा और दूसरा भाग बी व्यक्तित्व परीक्षण का होगा विषय अधिकतम. निशान अवधि सामान्य अध्ययन 200 अंक 3 घंटा। अंग्रेजी 200 अंक 2 घंटा। बीस मिनट। अंकगणित 100 अंक 4 घंटा। भाषा 100 अंक 2 घंटा। बीस मिनट। संचार कौशल और लेखन 200 अंक 2 घंटा। बीस मिनट। चरण 4 व्यक्तित्व परीक्षण एक बार जब आप अंतिम चरण से गुजर जाते हैं तो साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार में उम्मीदवारों से उनके व्यक्तित्व और मानसिक क्षमता का परीक्षण किया जाता है। फिर सफल उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार की जाती है सहायक प्रवर्तन नौकरी विवरण एक सहायक प्रवर्तन अधिकारी का काम दबाव और जिम्मेदारियों से भरा होता है, कभी-कभी उन्हें अपने सहयोगियों और यहां तक कि वरिष्ठों के साथ भी सख्ती से पेश आना पड़ता है जब वे स्वयंनिर्धारित नीतियों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं. इसलिए यह काम कठिन माना जाता है। लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए व्यक्ति को अपनी कार्य जिम्मेदारियों के प्रति बहुत समर्पित, बहादुर, मेहनती, ईमानदार और साथ ही व्यवहारकुशल होना होगा क्योंकि उसे कई उच्च प्रोफ़ाइल वाले लोगों से निपटना होगा जो खुद को बचाने के लिए उच्च पदों पर अपने प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं और बदले में अधिकारी को गलत या निष्पक्ष साबित करें। सहायक प्रवर्तन अधिकारी वेतन एक प्रवर्तन अधिकारी को 6500-10,500 रुपये का वेतनमान मिलता है। भारत सरकार ने विभिन्न पदों पर अपने कर्मचारियों के लिए वेतन ग्रेड तय किए हैं। हालांकि नए वेतन आयोग के साथ इनमें बदलाव होता रहता है. नोटः उपरोक्त वेतनमान केवल वेतनमान का एक अनुमान प्रदान करते हैं। सेवा की विभिन्न शाखाओं के वेतनमान अलग-अलग हैं। यहां तक कि एक ही शाखा के कर्मियों का वेतन उनकी पोस्टिंग के क्षेत्र और किसी विशेष समय पर उनके द्वारा संभाली गई जिम्मेदारी के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। वेतन के अलावा सहायक प्रवर्तन अधिकारी को विभिन्न प्रकार के भत्ते मिलते हैं जैसे महंगाई भत्ता, शहर प्रतिपूरक भत्ता, अवकाश यात्रा भत्ता, चिकित्सा और रियायती आवास।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023